राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 19 अगस्त 2026 वर्ष-9,अंक-197 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

अमेरिका में सौ से ज्यादा इंडस्ट्री लीडर्स से गुजरात सीएम की मुलाकात, राज्य को बेहतरीन ट्रेड पार्टनर बताया

गांधीनगर।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को अमेरिका में सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के 100 से ज्यादा लीडर्स के साथ कई राउंड-टेबल और वन-टू-वन मीटिंग की। उन्होंने राज्य को सिर्फ निवेश की जगह के तौर पर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सप्लाई-चेन डेवलपमेंट के लिए एक लंबे समय के रणनीतिक साझेदार के तौर पर पेश किया। अमेरिका यात्रा के दूसरे दिन, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडटेक, हेल्थटेक, गेमिंग और डीपटेक के लीडर्स के साथ बातचीत की। इस बातचीत में अमेरिकी कंपनियों और राज्य के बीच निवेश, रिसर्च, स्किलिंग और बिजनेस सहयोग के मौकों पर चर्चा हुई। पटेल ने कंपनियों को अगले साल जनवरी में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2027 में शामिल होने और बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) और बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (बी2जी) मीटिंग्स के जरिए संभावित पार्टनरशिप की संभावनाओं को तलाशने के लिए आमंत्रित किया। सेमीकंडक्टर और टेक्नोलॉजी लीडर्स के साथ बातचीत के दौरान, पटेल ने सिलिकॉन वैली की टेक्नोलॉजी क्षमताओं को गुजरात के इंडस्ट्रियल बेस के साथ जोड़ने की संभावना पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए एक पूरा इकोसिस्टम विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें आर एंड डी और इनोवेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल विस्तार तक सब कुछ शामिल है। पटेल ने कहा, ÷अगली पीढ़ी के टेक्नोलॉजी हब की सफलता न केवल इनोवेशन पर निर्भर करेगी, बल्कि जमीन, बिजली, कनेक्टिविटी, पूंजी, टैलेंट और पॉलिसी में स्थिरता जैसी सभी सुविधाओं की एक साथ उपलब्धता पर भी निर्भर करेगी। गुजरात यह सब कुछ उपलब्ध कराने और टेक्नोलॉजी-आधारित निवेश को आसान बनाने के लिए तैयार है।÷ मीटिंग्स में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और उभरती टेक्नोलॉजी में अपनी स्थिति मजबूत करने की राज्य की महत्वाकांक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।

गुजरात खुद को एक प्रमुख सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार ने हाल ही में इसे पॉलिसी में स्थिरता, इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) से प्रेरित चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए तेजी से आगे बढ़ते हब के तौर पर बताया है। मीटिंग्स में शामिल इंडस्ट्री प्रतिनिधियों ने गुजरात के इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी में स्थिरता, तेज मंजूरी प्रक्रियाओं और बिजनेस-फ्रेंडली व सक्रिय दृष्टिकोण की तारीफ की। एआई, हेल्थटेक, एडटेक और गेमिंग के लीडर्स के साथ एक अलग राउंड टेबल मीटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनरेटिव एआई, रोबोटिक्स, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी और गेमिंग के उभरते इस्तेमाल पर चर्चा हुई। भाग लेने वालों ने गुजरात में इन टेक्नोलॉजी के संभावित इस्तेमाल पर भी विचार किया। चर्चा में जेनरेटिव एआई मॉडल (लार्ज

लैंग्वेज मॉडल भी शामिल) और विज्ञापन, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो जनरेशन और शिक्षा में उनके इस्तेमाल पर बात हुई। गेमिंग भी चर्चा का एक अन्य विषय था, जिसमें मुख्यमंत्री और इंडस्ट्री लीडर्स ने गुजरात में इस सेक्टर को विकसित करने के मौकों पर विचार किया। चर्चा में गुजरात में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़े मौकों और सहायक पॉलिसी, इनोवेशन और ज्यादा इंडस्ट्री भागीदारी के जरिए गेमिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने की संभावना पर भी विचार किया गया।

जेजेएमपी के पांच लाख के इनामी रामदेव लोहरा समेत चार उग्रवादी गिरफ्तार

एक एके-47 राइफल समेत भारी मात्रा में हथियार, वॉकी-टॉकी, नौ मोबाइल जब्त

गुमला।

गुमला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठन के सबजोनल सदस्य रामदेव लोहरा उर्फ काका समेत चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में रामदेव लोहरा, अरविंद नायक, मुनेश्वर सिंह और जितेंद्र लोहरा शामिल हैं। रामदेव लोहरा पर झारखंड पुलिस ने पांच लाख रुपए का इनाम रखा है। पुलिस ने इनके पास से हथियार समेत अन्य सामान बरामद किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को प्रेस वार्ता में एसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जेजेएमपी से जुड़े कुछ उग्रवादी लातेहार से गुमला पहुंचे हैं और जिले में संगठन को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने उनकी गतिविधियों पर नजर रखी। इसके बाद डुमरी थाना क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर चारों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार रामदेव लोहरा जेजेएमपी के सबजोनल स्तर पर सक्रिय था और उस पर पांच लाख का इनाम घोषित है। अन्य गिरफ्तार आरोपियों की भी संगठन में अहम भूमिका बताई जा रही है। पुलिस इनसे पूछताछ कर संगठन के नेटवर्क और जिले में उनकी गतिविधियों से संबंधित जानकारी जुटा रही है। बताया गया कि जेजेएमपी सुप्रीमो रामदेव उरांव की गिरफ्तारी के बाद संगठन के सदस्य गुमला में अपनी गतिविधियों को फिर मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान कई हथियार सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। बरामद सामान की विस्तृत जानकारी एसपी ने दी। पुलिस अब संगठन से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है। एसपी ने कहा कि उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस का अभियान लगातार जारी रहेगा। इस कार्रवाई को गुमला पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। चार उग्रवादियों की गिरफ्तारी से जिले में जेजेएमपी के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। पुलिस को उम्मीद है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर संगठन के अन्य सदस्यों और उनकी गतिविधियों के बारे में अहम जानकारी मिल सकेगी। पुलिस ने गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से एक एके-56 राइफल व दो मैगजीन, एक एसएलआर राइफल व मैगजीन, एक सेमी-ऑटोमेटिक राइफल, एक 7.65 एमएम पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद किया है। इसके अलावा कई हथियारों के कुल 146 जिंदा राउंड, एक वॉकी-टॉकी, नौ मोबाइल फोन, दो वाई-फाई डोंगल, प्रतिबंधित जेजेएमपी/नक्सली पर्चे और एक बाइक बरामद की गई है।

कावेरी जल विवाद- तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, कहा- तय हिस्से से ज्यादा पानी मिल चुका

नई दिल्ली ।

कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों पर सवाल उठाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में कहा कि उपलब्ध आंकड़ों को कुल मिलाकर देखने पर ऐसा लगता है कि तमिलनाडु को उसके निर्धारित हिस्से से अधिक पानी मिल चुका है।

तमिलनाडु सरकार ने अदालत से कर्नाटक को अपने हिस्से का पानी तत्काल जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। राज्य का कहना था कि कम बारिश वाले साल में उसे कावेरी से पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है और इससे सिंचाई प्रभावित हो रही है। तमिलनाडु ने कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की अनुशंसित मात्रा और कर्नाटक से वास्तविक रूप से मिल रहे पानी को अपनी जरूरतों से कम बताया। कर्नाटक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि कावेरी बेसिन में पानी की भारी कमी है। उन्होंने अदालत को बताया कि तमिलनाडु को अब तक 14.814 टीएमसी पानी मिल चुका है। उनका कहना था कि मौजूदा परिस्थितियों और अनुपात के आधार पर पानी की उपलब्धता का आकलन किया जाना चाहिए। दीवान ने यह भी बताया कि कर्नाटक ने आने वाले दिनों में कम पानी की भरपाई करने का आश्वासन दिया है।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की एम्स में सफल एंजियोप्लास्टी, हालत स्थिर

नई दिल्ली ।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा की 17 अगस्त को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में सफल एंजियोप्लास्टी हुई है। एम्स अस्पताल ने पुष्टि की है कि प्रक्रिया के बाद उनकी हालत स्थिर है और वे कार्डियोलॉजी विभाग में डॉक्टरों की निगरानी में हैं। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बेचैनी महसूस होने के बाद नड्डा को 14 अगस्त को ऑब्जर्वेशन के लिए भर्ती किया था। इससे पहले, 13 अगस्त की शाम को उनकी कोरोनरी एंजियोग्राफी सहित कई व्यापक जांचें की गई थीं। अस्पताल ने बताया कि ये जांचें बेचैनी की शिकायत के बाद की गई थीं और वे अब ठीक महसूस कर रहे हैं।

दिल्ली पुलिस का सुप्रीम कोर्ट में जवाब,कहा- छात्रों पर कार्रवाई जरूरी थी

पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से किया इनकार

बैरिकेड तोड़ने और संसद की ओर बढ़ने की कोशिश के बाद बिगड़े हालात

नई दिल्ली ।

दिल्ली पुलिस ने छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक या गैरकानूनी बल प्रयोग के आरोपों से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में पुलिस ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुआ प्रदर्शन शुरुआत में शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में बैरिकेड तोड़ने और प्रदर्शनकारियों के संसद की ओर बढ़ने की कोशिश के बाद स्थिति हिंसक हो गई। पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए करीब 5,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। करीब 3 किलोमीटर के क्षेत्र में 30,000 से अधिक प्रदर्शनकारी मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि भीड़ के नियंत्रण से बाहर होने के बाद हालात संभालने के लिए चरणबद्ध तरीके से बल का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि नई दिल्ली जिले में उस दौरान बीएनएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू थे। प्रदर्शनकारियों को कई बार चेतावनी देकर वहां से हटने की अपील की गई, लेकिन पुलिस के अनुसार इन अपीलों को नजरअंदाज किया गया। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान कई स्थानों पर बैरिकेड तोड़े गए और कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। सरकारी संपत्ति को नुकसान

पहुंचाने के आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस ने कहा कि अन्य सभी उपायों के विफल होने के बाद ही न्यूनतम आवश्यक बल का इस्तेमाल किया गया। हलफनामे में टियर स्मोक और सीमित लाठीचार्ज के इस्तेमाल को भी उचित ठहराया गया है। पुलिस के अनुसार, इनका उद्देश्य भीड़ को तितर-बितर करना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना था। दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान 240 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं करीब 218 प्रदर्शनकारियों का मेडिको-लीगल परीक्षण कराया गया। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन स्थल पर सादे कपड़ों में अधिकारियों को 'स्पॉटर्स' के रूप में भी तैनात किया गया था।

नसीर मदनी का दावा- हाफिज सईद ने 10000 आतंकी कश्मीर भेजे थे

पूर्व सेना अफसर ने कसा तंज कहा- जल्द विदाई की कही बात

नई दिल्ली।

पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक कार्यक्रम का वीडियो सामने आया है। इस पर मौलवी नसीर मदनी ने कहा है कि हाफिज सईद ने कश्मीर में 10 हजार आतंकियों को भेजा था। इस बयान पर भारत के पूर्व सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडेय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मदनी के लिए 'सबसे जल्दी विदाई' की बात कहते हुए सीधा तंज कसा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पांडेय ने कहा कि जिन लोगों ने भारतीय सेना, चिनार कोर और जम्मू-कश्मीर पुलिस की कार्रवाई को देखा है, वे जानते हैं कि आतंकी किस अंजाम तक पहुंचते हैं। इसके बाद उन्होंने मदनी को भी 'सबसे जल्दी विदाई' के लिए आने की बात कही। नसीर मदनी कुछ समय पहले हार्ट अटैक को लेकर चर्चा में आया था। रिपोर्टों के मुताबिक वह जुलाई में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के जहानियां शहर में एक धार्मिक भाषण के दौरान गिर गया था और उसे अस्पताल ले जाया गया था। बाद में उसकी हालत स्थिर बताई गई। अब 14 अगस्त को बहावलनगर में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े कार्यक्रम में उसके मंच पर नजर आने की खबर सामने आई है।

मदनी ने भाषण में लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद की तारीफ की। इसी दौरान उसने दावा किया कि हाफिज सईद ने कश्मीर में 10 हजार आतंकियों को भेजा था। इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, बयान ने पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क और कश्मीर में आतंकवाद के पुराने संबंधों को फिर चर्चा में ला दिया है।

छात्रों के आगे झुकी सरकार,जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द

- 2014 से हुई सभी नियुक्तियों में गड़बड़ियों की होगी जांच

रांची ।

झारखंड सरकार ने लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को बताया कि राज्य कैबिनेट ने परीक्षा रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक भर्ती परीक्षाओं में हुई छोटी-बड़ी गड़बड़ियों और अनियमितताओं की व्यापक जांच कराने का भी निर्णय लिया है। फैसले के बाद आंदोलन कर रहे छात्रों में खुशी का माहौल देखा गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षाओं में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा संचालन के लिए पहले से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) मौजूद है। यदि उसका सही तरीके से पालन किया जाता तो कई गड़बड़ियों को रोका जा सकता था। अब सुधारों में जरूरी बदलाव जोड़ने पर विचार किया जाएगा। इसके लिए एक आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित करने का फैसला लिया गया है। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की ओर से एमएमडीआर एक्ट में किए गए संशोधनों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर जल्द बैठक कर विस्तार से विचार-विमर्श किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर केंद्र के संशोधनों पर चर्चा के लिए झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने

पर भी विचार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सुधार प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगी और परीक्षा व्यवस्था को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

छात्र नेता ने अनशन खत्म करने का ऐलान किया जेएसएससी-सीजीएल समेत टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के बाद छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने आंदोलन में सहयोग करने वाले छात्रों, अभिभावकों और अन्य लोगों का आभार जताया। उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री को भी छात्रों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने के लिए धन्यवाद दिया।

मथुरा में केमिकल से बन रहा था जहरीला पनीर, फैक्ट्री का भंडाफोड़

मथुरा ।

उत्तरप्रदेश के मथुरा जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने छाता इलाके में चल रही नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, जहां खतरनाक केमिकल्स और रिफाइंड ऑयल से पनीर तैयार हो रहा था। कार्रवाई के दौरान, मौके पर मिले लगभग 500 किलोग्राम जहरीले पनीर को तुरंत नष्ट किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1.05 लाख रुपये है। जिला प्रशासन अधिकारियों के अनुसार, सोनू कुमार नामक व्यक्ति की फैक्ट्री में पनीर बनाने के लिए रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, टीनोपाल केमिकल, आयरा और सोडियम हाइड्रो जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा था।

मनुष्य को स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए-पीएम मोदी

पीएम मोदी ने एक्स पर दिया एकजुटता पर जोर

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक प्रेरणादायी सुभाषित साझा किया, जिसमें आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने के महत्व पर बल दिया गया। उन्होंने संस्कृत का श्लोक, उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो ह्येव पौरुषम। अप्यपर्वणि भज्येत न नमत्वेव कस्यचित॥ साझा किया। इस श्लोक का हिंदी अर्थ है कि मनुष्य को सदैव अपने आत्मसम्मान, साहस और स्वाभिमान के साथ जीवन जीना चाहिए। सच्चा पुरुषार्थ और पराक्रम इसी में है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता न करे, बल्कि सत्य, धैर्य और आत्मगौरव के साथ अपने आदर्शों पर दृढ़ रहे। यह संदेश राष्ट्र निर्माण में नैतिक मूल्यों और व्यक्तिगत दृढ़ता की भूमिका को रेखांकित करता है।

इससे ठीक एक दिन पहले, सोमवार को भी प्रधानमंत्री ने सुभाषित के माध्यम से सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति का आह्वान किया था। उन्होंने लिखा था, सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही देश आगे बढ़ता है। यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। इसके साथ ही उन्होंने एक श्लोक, समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति॥ भी साझा किया था, जिसका हिंदी अर्थ है कि हम सबके संकल्प एक समान होने चाहिए, हमारे मन एकता के भाव से जुड़े होने चाहिए, जिससे हम सभी परस्पर सहयोग तथा समान व्यवहार के साथ समाज की उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। इन संदेशों के जरिए प्रधानमंत्री लगातार समाज में सकारात्मक सोच और सहभागिता को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर भी इसी तरह का प्रेरणादायी सुभाषित साझा किया था। तब उन्होंने उन सभी देशवासियों को हृदय से नमन किया था, जिन्होंने उस वीभत्स दौर से निकलकर देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने अपने साहस और सामर्थ्य से दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी संकल्पों को सिद्ध किया जाता है और सद्भावना तथा एकजुटता की राष्ट्रीय भावना को सशक्त करने का आग्रह किया था।

इस अवसर पर साझा किया गया श्लोक था, उद्यमस्य प्रसादेन दृश्यन्ते विविधाः कलाः। कातरा एव जल्पन्ति यद् भाव्यं तद् भविष्यति॥ जिसका हिंदी अर्थ है

कि परिश्रम, उद्यम और पुरुषार्थ से ही विविध कलाएं, विज्ञान, तकनीकी कौशल, शिल्प तथा नवाचार विकसित होते हैं और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

वंदेमातरम क्यों बना राजनीतिक विवाद का विषय?

(लेखक-सौरभ वार्ष्णेय)

वंदेमातरम केवल दो शब्दों का उच्चारण नहीं है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों, राष्ट्रभक्ति की भावना और उस दौर के संघर्ष का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसके गायन से देशभक्ति से वातावरण भी गुंजायमान हो जाता है। जिस गीत ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय चेतना जगाने में भूमिका निभाई, वह आज राजनीतिक बहस और विवाद का विषय बन गया है। सवाल यह नहीं है कि वंदेमातरम् का सम्मान होना चाहिए या नहीं—उसका सम्मान भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निर्विवाद रूप से होना चाहिए। असली सवाल यह है कि आखिर एक राष्ट्रीय भावना से जुड़े गीत को बार-बार राजनीतिक विवाद के केंद्र में क्यों खड़ा कर दिया जाता है? अभी 15 अगस्त को कांग्रेस के कार्यालय में फिर से इसको लेकर विरोधियों ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। यानी देशभक्ति को भी तराजू में तोला जा रहा है। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह सह नहीं है। आज देश 80 वां स्वतंत्रता दिवस मना चुका है। आगामी दिवस जब 21 साल बाद देश 100 वां स्वतंत्रता दिवस मनायेगा तब भी हम देश को उंचाइयों पर ले जाने की जगह यह विवाद कर रहे होंगे। आज के राजनेताओं को देश के लिए कुछ सोचना होगा। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी विविधता है। यहां अनेक धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, परंपराएं और विचारधाराएं सदियों से साथ-साथ रही हैं। स्वतंत्रता आंदोलन ने भी इसी विविधता को एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य में जोडने का काम किया था। वंदेमातरम् उसी दौर की राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण स्वर था। इसलिए जब इसे राजनीतिक बयानबाजी का हथियार बनाया जाता है, तो केवल एक गीत पर विवाद नहीं होता, बल्कि उस व्यापक राष्ट्रीय भावना पर बहस खड़ी हो जाती है, जिसने देश को स्वतंत्रता के संघर्ष में एकजुट किया था।

वंदेमातरम् की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित यह गीत उन्नीसवीं सदी के अंतिम दौर में सामने आया। बाद में यह स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय चेतना का महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे उत्साह और संघर्ष की भावना के साथ अपनाया। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलनों में इसके उद्घोष ने लोगों में राष्ट्रीय भावना पैदा की। यही कारण है कि वंदेमातरम् को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है।

लेकिन इतिहास के साथ-साथ उस समय की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भी समझना होगा। भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज था। राष्ट्रवादी आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए यह आवश्यक था कि देश के सभी समुदायों को उसमें बराबर का स्थान महसूस हो। वंदेमातरम् के कुछ अंशों की धार्मिक प्रतीकात्मकता को लेकर समय-समय पर आपत्तियां भी सामने आईं। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस ने 1937 में यह निर्णय लिया कि सार्वजनिक अवसरों पर गीत के शुरुआती दो पदों का उपयोग किया जाए, जिन्हें अपेक्षाकृत अधिक स्वीकार्य माना गया। यह निर्णय बताता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व ने भी राष्ट्रीय एकता और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया था।

स्वतंत्र भारत में भी वंदेमातरम् को विशेष सम्मान मिला। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रगान के समान सम्मान देने की बात स्वीकार की। वहीं जन गण मन' को राष्ट्रगान और वंदेमातरम् को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। यानी भारत के संवैधानिक और राष्ट्रीय जीवन में दोनों की अपनी विशिष्ट पहचान बनी। समस्या तब पैदा होती है, जब इस ऐतिहासिक संतुलन को राजनीतिक बहस में बदलकर यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि कौन अधिक राष्ट्रवादी है और कौन कम।

राष्ट्रभक्ति किसी एक गीत, नारे या प्रतीक तक सीमित नहीं हो सकती। देश के प्रति सम्मान का अर्थ संविधान के प्रति निष्ठा, कानून का सम्मान, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, कर्तव्यों का पालन और राष्ट्रहित में ईमानदार योगदान भी है। यदि कोई व्यक्ति वंदेमातरम् का सम्मान करता है तो यह उसकी राष्ट्रभक्ति की अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति की राष्ट्रभक्ति को केवल इस आधार पर मापना कि वह किसी विशेष अवसर पर किस तरह का नारा लगाता है, लोकतांत्रिक समाज के लिए स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर, यह भी सही है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान की भावना समाज में बनी रहनी चाहिए। किसी राष्ट्रीय गीत या स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रतीक का जानबूझकर अपमान करना भी उचित नहीं है। लोकतंत्र का अर्थ केवल अधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। इसलिए वंदेमातरम् के सम्मान और उसके राजनीतिक दुरुपयोग—दोनों के बीच स्पष्ट अंतर करना होगा।

आज राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे इतिहास को समझें, उसे चुनावी हथियार न बनाएं। वंदेमातरम् पर बहस यदि इतिहास, साहित्य, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में हो तो वह सार्थक हो सकती है। लेकिन यदि इसका इस्तेमाल विरोधी दल या किसी समुदाय को राष्ट्रविरोधी साबित करने के लिए किया जाए तो यह बहस समाज को जोडने के बजाय विभाजित करेगी। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है—क्या राष्ट्रवाद का अर्थ केवल भावनात्मक नारों तक सीमित हो जाना चाहिए? यदि देश में बेरोजगारी है, किसान अपनी आय को लेकर चिंतित है, युवा बेहतर शिक्षा और रोजगार की तलाश में है, सीमाओं की सुरक्षा चुनौतीपूर्ण है, शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है और गरीब व्यक्ति सम्मानजनक जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए काम करना भी राष्ट्रभक्ति है। सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करता है, किसान खेत में अन्न पैदा करता है, शिक्षक नई पीढ़ी तैयार करता है, वैज्ञानिक अनुसंधान करता है और श्रमिक अपने श्रम से अर्थव्यवस्था को गति देता है। इन सभी के योगदान में राष्ट्रभक्ति दिखाई देती है।

दुर्भाग्य से हमारी राजनीतिक बहस में कई बार वास्तविक मुद्दों की जगह प्रतीकों को केंद्र में लाने की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई देती है। प्रतीकों की अपनी भूमिका है, लेकिन प्रतीक तभी सार्थक होते हैं जब उनके पीछे की भावना और जिम्मेदारी को भी समझा जाए। वंदेमातरम् का मूल संदेश मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना से जुड़ा है। यदि हम इस भावना को समझ लें तो विवाद अपने आप छोटा हो सकता है। यह भी विचार करने की जरूरत है कि किसी राष्ट्रीय प्रतीक के प्रति सम्मान स्वाभाविक होना चाहिए, राजनीतिक दबाव का परिणाम नहीं। देशभक्ति को आदेश से पैदा नहीं किया जा सकता। वह नागरिक के मन में इतिहास, शिक्षा, संस्कार और देश के प्रति अपनेपन की भावना से विकसित होती है। जब राष्ट्रप्रेम को राजनीतिक पहचान की कसौटी बना दिया जाता है, तब लोकतांत्रिक समाज में अनावश्यक तनाव पैदा होना स्वाभाविक है।

वंदेमातरम के संदर्भ में राजनीतिक दलों को भी संयम दिखाना चाहिए। सत्ता पक्ष को यह समझना होगा कि राष्ट्रवाद किसी एक दल की संपत्ति नहीं है। विपक्ष को भी यह समझना होगा कि ऐतिहासिक राष्ट्रीय प्रतीकों को केवल राजनीतिक विरोध के लिए खारिज करना उचित नहीं है। दोनों पक्षों को इतिहास के प्रति सम्मान और वर्तमान के प्रति जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की राष्ट्रीय पहचान बहुस्तरीय है। इसमें वंदेमातरम है, जन गण मन है, तिरंगा है, संविधान है और स्वतंत्रता आंदोलन की असंख्य स्मृतियां हैं। इसमें शहीदेआजम भगत सिंह का साहस है, महात्मा गांधी का सत्याग्रह है, सुभाषचंद्र बोस का संघर्ष है, सरदार पटेल की एकता की भावना है और डॉ. आंबेडकर द्वारा निर्मित संवैधानिक लोकतंत्र की दृष्टि भी है। भारत को इनमें से किसी एक प्रतीक में सीमित नहीं किया जा सकता। वंदेमातरम पर विवाद खड़ा करने से पहले हमें यह पूछना चाहिए कि क्या हम उस भारत की भावना को समझ रहे हैं, जिसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था? वह भारत ऐसा था जिसमें विभिन्न समुदायों ने मिलकर विदेशी शासन का मुकाबला किया। स्वतंत्रता का संघर्ष किसी एक जाति, धर्म या भाषा का संघर्ष नहीं था। वह पूरे भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन था। आज आवश्यकता इस बात की है कि वंदेमातरम् को विवाद का विषय बनाने के बजाय इतिहास और राष्ट्रीय चेतना के सम्मान के रूप में देखा जाए। जहां सम्मान आवश्यक है, वहां सम्मान हो; जहां संवैधानिक स्वतंत्रता का प्रश्न है, वहां संविधान सर्वोपरि हो; और जहां राजनीतिक मतभेद हों, वहां लोकतांत्रिक संवाद हो।

वंदेमातरम का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब उसके नाम पर समाज में दूरी नहीं, बल्कि देश के प्रति साझा जिम्मेदारी की भावना मजबूत हो। राजनीति को राष्ट्रभावना से प्रेरणा लेनी चाहिए, राष्ट्रभावना को राजनीति का हथियार नहीं बनाना चाहिए। भारत की शक्ति उसकी विविधता में है और उसकी लोकतांत्रिक परंपरा का मूल संदेश भी यही है कि असहमति के बावजूद देश सबसे ऊपर रहे। इसलिए समय आ गया है कि वंदेमातरम को लेकर होने वाली बहस नारों की राजनीति से ऊपर उठे। इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ा जाए, राष्ट्रीय प्रतीकों को सम्मान दिया जाए और लोकतांत्रिक अधिकारों को भी उतनी ही गंभीरता से समझा जाए। आखिरकार राष्ट्र केवल गीतों और नारों से नहीं बनता—राष्ट्र नागरिकों के विश्वास, संविधान की मर्यादा, सामाजिक सद्भाव और करोड़ों लोगों के ईमानदार योगदान से बनता है। वंदेमातरम् पर बहस हो तो भारत को जोडने के लिए हो, बांटने के लिए नहीं। यही उस गीत की ऐतिहासिक भावना के प्रति सच्चा सम्मान होगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।)

संपादकीय

नबीन के नगीने

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नये बदलाव के जरिये एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। कार्यकारिणी में उ.प्र. के पदाधिकारियों का दबदबा, अपेक्षाकृत युवाओं को तरजीह तथा आईटी सेल के शीर्ष पद में बदलाव बताता है, ये परिवर्तन समय की जरूरत है। कहीं न कहीं जेन-जी आंदोलन के बाद पार्टी ने बदलाव की आकांक्षी नई पीढ़ी से जुड़ने का मन बनाया है। छात्र आंदोलन में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका को महसूस करते हुए एक दशक के बाद भाजपा के आईटी हेड अमित मालवीय की विदाई हुई है और दीपक म्हस्के की एंट्री हुई है। कैमिस्ट्री के प्रोफेसर रहे म्हस्के चुनावी आंकड़ों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संबंधित डेटा विश्लेषण अभियान से जुड़े रहे हैं। छत्तीसगढ़ आईटी सेल के समन्वयक रहे म्हस्के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने और विभिन्न क्षेत्रों में व्हाट्सऐप समूहों का नेटवर्क तैयार करने के लिये पहचान रखते हैं। दरअसल, पार्टी वार-प्रतिवार के दौर से आगे निकलकर क्षेत्र, आयु समूह व मुद्दों के जरिये जनता का मूड भांपने का प्रयास करेगी। निस्संदेह, यह निर्णय राजनीति में सोशल मीडिया की बदलती भूमिका को भी दर्शाता है। पार्टी ने महसूस किया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म अब सिर्फ प्रचार का जरिया ही नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक असंतोष से मुकाबले तथा आम लोगों से जुड़ने का भी माध्यम बना है। पार्टी ने यह भी महसूस किया कि हालिया छात्र आंदोलन में छोटे वीडियो, व्यंग्य, राजनीतिक मीम व वायरल सामग्री की लोगों को जोड़ने में बड़ी भूमिका रही है। वहीं दूसरी ओर भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उ.प्र. में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उ.प्र. का दबदबा नजर आता है। जिन आठ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उनमें राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में स्मृति ईरानी की वापसी सुर्खियों में है। साथ ही राजनीतिक समीकरण साधने के लिये ओबीसी से लेकर अल्पसंख्यक चेहरे कार्यकारिणी में उ.प्र. से शामिल किए गए है। कह सकते हैं राजनीति के साथ ही सामाजिक समीकरण भी साधने की कोशिश हुई है। बहरहाल, नितिन नबीन की नई कार्यकारिणी में महामंत्री के रूप में स्मृति ईरानी की वापसी ने खासी सुर्खियां बटोरी हैं क्योंकि अमेठी से चुनाव हारने के बाद उन्हें हाशिये पर माना जा रहा था। एक समय राहुल गांधी को हराकर अमेठी से सांसद और मंत्री बनने के बाद वे लगातार सुर्खियों में रही थीं। वहीं कुर्मी समाज से आने वाली रेखा वर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं दलित समुदाय से आने वाले बुलंदशहर के सांसद डॉ.भोला सिंह राष्ट्रीय सचिव, प्रभावी यादव समाज से आने वाली आजमगढ़ की संगीता यादव के जरिये आगामी विधानसभा चुनाव में सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश हुई है। उत्तर प्रदेश से ही अमरपाल मौर्य को राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरी ओर उ.प्र. के ही कुंवर बासित अली को अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान दी गई है। जो संगठनात्मक रणनीति के साथ ही इन समाजों में पकड़ मजबूत करने की कोशिश भी है। इसे उ.प्र. में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारी माना जा रहा है। निस्संदेह, यह कहावत सटीक है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उ.प्र. से होकर ही जाता है।

तुलसीदास जयंतीः भक्ति, संस्कृति और मानवता का उत्सव

(लेखक -लक्ष्मी कांत शर्मा)

तुलसीदास जयंती सिर्फ कवि की जन्मतिथि की याद है; यह एक अवसर है कि भारतीय समाज का सांस्कृतिक आत्मबोध करें, जिसमें भाषा, लोकजीवन, भक्ति और मानवीय मर्यादा एक-दूसरे से जुड़े हैं। अपने काव्य में गोस्वामी तुलसीदास ने धर्म को केवल पूजा-पाठ तक नहीं सीमित रखा, बल्कि उसे आचरण, करुणा, उत्तरदायित्व और लोकमंगल से जोड़ा। इसलिए, मंदिरों और धार्मिक कार्यक्रमों तक सीमित रहने के बजाय उनकी जयंती एक सांस्कृतिक पर्व बन सकती है जो लोगों को धार्मिक चेतना देता है। तुलसीदास ने सोलहवीं शताब्दी में उत्तर भारत में जन्म लिया, जहां राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता, जातिगत विभाजन और धार्मिक तनाव थे। उसकी जीवनी बातों पर विद्वानों के बीच मतभेद हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपने काव्य-दृष्टिकोण को साधना, जनसंपर्क और व्यक्तिगत अभाव से बनाया। वे शास्त्र-परंपरा से परिचित थे, लेकिन जनभाषा में ज्ञान देना उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। उन्हें अपने समय के आम लोगों की चिंताओं, आकांक्षाओं और नैतिक प्रश्नों को कथा और कविता में उतारा कि उनका साहित्य आम लोगों की जीवनशैली का एक अंग बन गया।

रामचरितमानस की भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। तुलसीदास ने संस्कृत में प्रतिष्ठित रामकथा को अवधी में लिखकर ज्ञान और जनसामान्य के बीच खड़ी भाषा की दीवार को कम किया। यह सिर्फ भाषिक बदलाव नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक लोकतंत्रीकरण की एक बड़ी कोशिश भी थी। घरों, मंदिरों, मेलों, लोकनाट्यों और सामुदायिक पाठों में मानस की चौपाइयाँ गूंजती रहीं। इस ग्रंथ से पारिवारिक परंपरा, लोकगीतों की भावना, रामलीला की परंपरा तक प्रभावित हुई। तुलसीदास ने पुस्तकालय से साहित्य निकालकर चौपाल, आँगन और आम लोगों तक पहुँचाया।

तुलसीदास का भक्ति आंदोलन में योगदान भी इसी तरह है। भक्ति केवल भाव-विभोरता नहीं है; यह एक व्यक्ति को विनम्रता, अनुशासन और सेवा की चेतना भी देता है। ईश्वर से निकटता का मतलब मनुष्य से दूर रहना नहीं है, बल्कि उसके दर्द को समझना है। परहित सरिस धरम नहि भाई, पर पीड़ा सम नहि अधमाई की पंक्ति उनके मानवीय दृष्टिकोण का सार है। इसमें धर्म की कसौटी कर्मकांड नहीं है; बल्कि, यह दूसरों के हित और दर्द को समझने के लिए है। यही कारण है कि तुलसी की भक्ति लोकमंगल से जुड़ी हुई है और लोगों को अपने व्यवहार की जांच करने को प्रेरित करती है।

तुलसीदास के राम सिर्फ धार्मिक मानसिकता का प्रतीक नहीं हैं। वे धैर्य, मर्यादा, कर्तव्य और करुणा के आदर्श हैं। उनके चरित्र में अधिकार से अधिक जिम्मेदारी, जीत से अधिक नियंत्रण और सत्ता से अधिक जनहित पर बल है। भरत का त्याग, हनुमान की निस्वार्थ सेवा, शबरी की सहज श्रद्धा और केवट की आत्मीयता कथा को मानवीय संबंधों की कई परतों से भर देते हैं। इन घटनाओं का मूल्य यह है कि वे व्यक्ति की गरिमा को उसके भावों, कर्मों और चरित्र से नहीं, बल्कि उसके जन्म, पद और संपत्ति से जोड़ते हैं।

आज, हालांकि तकनीक में सुधार हो रहा है, लेकिन नैतिक असमंजस, सामाजिक विभाजन, आक्रामक भाषा, अहंकार और बढ़ती असंवेदनशीलता भी हैं। असहमति अक्सर द्वेष में बदल जाती है जब सार्वजनिक बहस होती है; सफलता की दौड़ में संबंध, नियंत्रण और उत्तरदायित्व खो जाते हैं। तुलसी साहित्य ऐसे वातावरण में हमें याद दिलाता है कि शक्ति का मूल्य तभी है जब वह नियंत्रित है; ज्ञान का मूल्य विनम्रता में है; और धर्म तभी जीवंत है, जब लोगों को दूसरों के प्रति दयालु बनाया जाता है। तुलसी का संदेश पलायन नहीं सिखाता; इसके बजाय, यह आपको अपने भीतर की अव्यवस्था को नियंत्रित करने और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है।

तुलसीदास को फिर से पढ़ने के लिए आलोचनात्मक विवेक भी आवश्यक है। प्रत्येक बड़ी रचना अपने काल की परिस्थितियों और सीमा से जुड़ी है। यही कारण है कि उनके लेखों को अनदेखा करके नहीं पढ़ना चाहिए, न ही कुछ विवादित पंक्तियों के आधार पर पूरी परंपरा को खारिज कर देना चाहिए। वर्तमान समय में न्याय, गरिमा और समानता के बारे में बातचीत करना और उनके साहित्य में निहित स्थायी मानवीय मूल्यों को समझना सही दृष्टिकोण होगा। रचनाकारों से प्रश्न पूछने और उनसे कुछ सीखने का साहस रखने वाले लोगों को सम्मान देना सही है।

युवा पीढ़ी के लिए तुलसी साहित्य महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस को तेज सूचना-प्रवाह और छोटे संदेशों की दुनिया में धैर्यपूर्वक पढ़ने का अवसर मिलता है; यह आपको कथा की नैतिक जटिलताओं को समझने और भाषा की लय को महसूस करने का अवसर देता है। यह युवाओं को बताता है कि नेतृत्व केवल आदेश देने का नाम नहीं है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता है; मित्रता सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि विपरीत परिस्थितियों में सहयोग करने की प्रतिज्ञा है; और सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है; यह भी समाज के प्रति कर्तव्य है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में तुलसी साहित्य को परीक्षा के पाठ के रूप में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए; इसे भाषा, संस्कृति, नैतिक दर्शन और सामाजिक इतिहास का जीवंत स्रोत मानना चाहिए।

तुलसीदास जयंती मनाने का सबसे अच्छा तरीका उनके मूल संदेश को व्यवहार में उतारना है, न कि पुष्पांजलि, शोभायात्रा या पाठ का आयोजन करना है। उनके साहित्य से व्यावहारिक शिक्षाएँ मिलती हैं, जैसे परिवार में चर्चा, समाज में सहिष्णुता, कमजोर के प्रति करुणा, सार्वजनिक जीवन में मर्यादा और मतभेद का सम्मान। यदि हम जयंती के अवसर पर अपने शब्दों, व्यवहार और सामाजिक उत्तरदायित्व की ईमानदार समीक्षा कर सकें, तो यह आयोजन वास्तव में जीवंत हो जाएगा।

तुलसीदास एक ऐसे भारतीय कवि हैं जिन्होंने भक्ति को मानवता, भाषा को लोकचेतना और कथा को आत्ममंथन से जोड़ा। उन्हें याद करना हमें अतीत को गौरव देने से अधिक वर्तमान को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। तुलसी की स्मृति उत्सव से आगे बढ़कर संस्कार बनेगी जब समाज विभाजन से ऊपर उठकर परहित, करुणा और मर्यादा को जीवन का आधार बनाएगा। इस उत्सव का असली संदेश है- मनुष्य को मानव से जोड़ना और संस्कृति को संवेदना में बदलना

लेखकः - लक्ष्मी कांत शर्मा, शिक्षक,शास. पूर्व माध्य. विद्यालय खपरीकला, डोंगरगांव, जिला राजनांदगाव (छ. ग.)

ध्वनि तंरगों से रोगें का उपचार

यह बात जान कर आप सभी को आश्चर्य होगा की ध्वनि तंरगें से भी रोगों के उपाच होते है। यह विश्व जीवों से भरा है। ध्वनि तंरगों की टकराहट से सुक्ष्म जीव मर जाते है, रात्री में सूर्य की पराबैगनी किरणां के अभाव में सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते है जो ध्वनि तरगों की टकराहट से मर जाते है। ध्वनि तरगों से जीवों के मरने की खोज सर्वप्रथम बर्लिन विश्वविधालय में 1928 में हुई थी। शिकागों के डॉ.ब्राइन ने ध्वनि तरगों से जीवों के नष्ट होने की बात सिद्ध की है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि शंख और घण्टा की ध्वनि लहरों से 27 घन फुट प्रति सेकिंड वायु शक्ति वेग से 1200फुट दूरी के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते है।

पूर्व में मंदिरों का निमार्ण गुम्वजाकार होता था दरवाजे छोटे होते थे अन्दर की ध्वनि बाहर नही निकलती थी, बाहर की ध्वनि अन्दर प्रवेश नही करती थी। मन्दिर में एक ईष्ट देव की प्रतिमा, एक दीपक, एक घण्टा, शंख होता था। यहां कोई भी रोगी श्रद्धा से जाता घण्टा या शंख ध्वनि कर दीप जलता बैठ कर श्रद्धा से प्रार्थना भक्ति करता, मौन ध्यान करता। रोंगों के ठीक होने की कामना करता वह ठीक हो जाता था। इसका बैज्ञानिक कारण घण्टा -शंख ध्वनि भक्ति प्रार्थना की ध्वनि तंरगें बाहर न जाकर गुम्वजाकार शिखर से टकराकर शरीर से टकराती जिससे शरीर के रोगाणु नष्ट हो जाते रोग ठीक हो जाते। आज भी पुराने मंदिरों में यह होता है। इसलिये सीमित मात्रा में बोलना ठीक है। ध्वनि ज्यादा मात्रा में प्रदूषण का रूप ले लेती है, जो शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से हानिकारक होती है। मौन रहने में ही सुख एवं सुख मय जीवन है।

विचार मंथन

अपराध में लिप्त नेता बना रहे हैं कानून? यह कैसा लोकतंत्र

(लेखक- सनत जैन)

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में राजनीति के अपराधीकरण को लेकर जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके अनुसार 543 में से 251 सांसदों पर अपराधिक मामले दर्ज हैं। यह सभी मामले एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे हैं। इन मामलों की संख्या 4000 से ज्यादा है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में सांसद और विधायक धड़ाधड़ कानून पर कानून बना रहे हैं। अब तो बिना बहस के और बिना प्रक्रिया के सदन के अंदर बिल प्रस्तुत कर दिए जाते हैं और उन्हें हो-हल्ले के बीच में सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर पास कर लिया जाता है। आसंदी में विराजमान पीठासीन अधिकारी इन्हें पास भी कर देते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में पहले जब कोई कानून बनता था उसके पहले सभी सदस्यों को निर्धारित समय के अंदर उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी जाती थी। कार्य मंतृणा की बैठक में उसके लिए समय निर्धारित किया जाता था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद अथवा विधायक अपनी राय रखते थे। सदन यदि सहमत होता था तो संशोधन पर भी चर्चा होती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह सारी प्रक्रिया खत्म होती जा रही है। आसंदी पर सरकार का दबाव रहता है। बिल पास करने के लिए जिस तरह की राजनीतिक कूटनीति सदन के अंदर होती है, उसने जिन लोगों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं उनकी सहभागिता एक तरह से खत्म हो गई है। जिसकी सरकार होती है वह मनमाने तरीके से कानून बना लेता है और वह कानून जबरिया लाद दिए जाते हैं।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है यदि कानून आम जनता स्वीकार नहीं करती है ऐसी स्थिति में कानून का पालन करना बड़ा कठिन हो जाता है। अदालतों में मुकदमों की संख्या बढ़ जाती है। आम जनता और सरकार दोनों मुकदमेबाजी में उलझ जाती है। सरकार और आम लोगों का पैसा खर्च होता है। वहीं न्यायपालिका भी समय पर न्याय नहीं कर पाती है। जिसके कारण संविधान और लोकतंत्र की जो मान्य परंपराएं थीं वह धीरे-धीरे खत्म होती जा रहे हैं। संसद और विधानसभा के सत्र बहुत छोटे होते जा रहे हैं। अब तो सांसद और विधायक जो अपने क्षेत्र से संबंधित बात सदन में रखते हैं उनमें भी चर्चा नहीं हो पा रही है। सांसद और विधायक केवल वेतन लेने वाले बन गए हैं। जब से दल-बदल कानून लागू हुआ, सचेतक और विहिप की व्यवस्था आई है उसके बाद सांसद और विधायकों की स्वतंत्रता भी खत्म हो गई है। वह ना तो अपनी बात कह सकते हैं और यदि वह कानून से सहमत नहीं हैं ऐसी स्थिति में उन्हें पार्टी विहिप के अनुसार मतदान करना पड़ता है। जिसके कारण सांसदों और विधायकों की स्वतंत्रता भी एक तरह से खत्म हो गई है। वह स्वतंत्र रूप से अपनी राय भी सदन के अंदर नहीं रख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था विशेष अदालतों के माध्यम से एक साल से कम समय में सांसद और विधायकों के मामलों का निपटारा किया जाएगा। सदन के अंदर ऐसे अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। लेकिन उनको प्रधानमंत्री बने 12 साल से अधिक हो चुके हैं, विशेष अदालतें भी काम कर रही हैं। इसके बाद भी अपराधियों की संख्या बढ़ती ही चली जा रही है। यह चिंता का विषय है। 28 में से 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी न्यायालय में आपराधिक मामले वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी जो रिपोर्ट पेश हुई है उसमें उत्तर प्रदेश की जानकारी शामिल नहीं है, इसकी जानकारी आने के बाद यह संख्या और भी बढ़ सकती है। सरकार को सोचना होगा जो भी कानून बनते हैं कानून बनने और लागू होने के साथ ही बड़ी तेजी के साथ मुकदमों की संख्या क्यों बढ़ रही है? कहा जाता है 60 फ़ीसदी से ज्यादा मामलों में सरकार के खिलाफ मुकदमे दायर होते हैं। भारत में सरकार ही सबसे बड़ी मुकदमेबाज है। एक-एक पेशी में लाखों रुपए की फीस सरकार अधिवक्ताओं को देती है। जबकि उसके पास अधिवक्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज होती है। उसके बाद भी सरकारों का खर्च वकीलों के रूप में बढ़ता ही चला जा रहा है। अब तो बड़े-बड़े वकील राजनीतिक आधार पर सुप्रीम कोर्ट छोड़कर हाईकोर्ट में पैरवी करने जा रहे हैं। इसने स्थिति को और भी विकट बना दिया है। केंद्र सरकार को इस मामले में गंभीरता से विचार करना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को भी जब संविधान ने यह अधिकार दिए हैं की जो भी कानून पास होते हैं वह मौलिक अधिकारों के दायरे में हों। जिस वर्ग के लिए कानून बनाए जा रहे हैं उनका व्यावहारिक स्वरूप हो कानून इस तरीके से बने कि उसमें सभी पक्ष संतुष्ट हों। जल्दबाजी में जो कानून बनाए और लागू किये जा रहे हैं उसके कारण न्यायपालिका में मुकदमों की बाढ़ आ गई है। अब तो संवैधानिक मामले भी सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष से ज्यादा से लंबित पड़े हुए हैं। उनकी सुनवाई का नंबर नहीं आ पा रहा है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यही कहा जा सकता है। यदि यही हाल कुछ साल और रहा तो कानून का राज है यह कहना बंद करना पड़ेगा। कई मामलों में तो आदमी को मरने के बाद न्याय मिलता है। बोफोर्स का अंतिम फैसला लगभग 40 साल के बाद मिला है। इसमें सरकार के अरबो रुपए खर्च हुए। इसी तरह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु के बाद अदालत ने उन्हें निर्दोष घोषित किया। मरने के बाद यदि इस तरह के फैसले मिले तो इन फैसलों का कोई औचित्य नहीं है। न्यायपालिका को इस दिशा में गंभीरता के साथ विचार करना होगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सोना-चांदी धड़ाम! एक दिन में 3,500 रुपए तक टूटे दाम

सोना 1,55,070 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी का भाव 2,35,450 रुपए प्रति किलोग्राम

नई दिल्ली ।

सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बाजार खुलते ही सोने के दाम 1,000 रुपये तक और चांदी 2,600 रुपये तक नीचे आ गई। सुबह एक घंटे के भीतर दोनों कीमती धातुओं में करीब 3,500 रुपये तक की गिरावट देखी गई, जिसने सोमवार की पूरी बढ़त को खत्म कर दिया। घरेलू वायदा बाजार मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सुबह बाजार खुलने के बाद 5 अक्टूबर की डिलीवरी वाला सोना 870 रुपये की गिरावट के साथ 1,55,070 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। वहीं 4 सितंबर की डिलीवरी वाली चांदी में 2,598 रुपये की कमी आई और यह 2,35,450 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर कारोबार कर रही थी। मंगलवार को सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 15,589 रुपये प्रति ग्राम रहा, जबकि 22 कैरेट सोना 14,290 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना 11,692 रुपये प्रति ग्राम पर बिका। चांदी का भाव 250 रुपये प्रति ग्राम और 2.50 लाख रुपये प्रति किलोग्राम रहा। देश के अलग-अलग शहरों में सोने-चांदी की कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिला।सतीश

भारत सरकार ने 400 टन चांदी आयात को दी मंजूरी

जयपुर ।

नए लाइसेंसिंग नियमों के कारण करीब छह महीने तक प्रभावित रहने के बाद भारत में चांदी का आयात अब धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। घरेलू बाजार में अंतरराष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले चांदी के ऊंचे भाव और आगामी त्योहारों व शादियों के सीजन को देखते हुए आयात में तेजी आई है। गुजरात की गिफ्ट सिटी स्थित इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के जरिए अब तक 89.81 टन चांदी भारत पहुंच चुकी है। वहीं सरकार ने कारोबारियों और बैंकों को करीब 400 टन चांदी के आयात के लिए लाइसेंस मंजूर किए हैं। चांदी की मांग बढ़ने के पीछे राखी, गणेश चतुर्थी और नवरात्र जैसे त्योहारों के साथ-साथ दिवाली और शादी का सीजन प्रमुख कारण हैं। इसके अलावा चांदी के सिक्कों, उपहारों और अन्य उत्पादों की मांग भी बढ़ी है। आयात बढ़ने से घरेलू बाजार में चांदी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद है।

आईनॉक्स क्लीन एनर्जी ने वेना एनर्जी का 6,000 करोड़ में अधिग्रहण किया

नई दिल्ली ।

आईनॉक्स क्लीन एनर्जी ने ब्लैकरॉक के स्वामित्व वाली जीआईपी की वेना एनर्जी इंडिया होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड का करीब 6,000 करोड़ रुपये में अधिग्रहण पूरा कर लिया है। वेना एनर्जी इंडिया, वेना समूह का भारत में नवीकरणीय ऊर्जा मंच है। कंपनी के मंगलवार को जारी बयान के अनुसार कई हितधारकों और वित्तपोषण भागीदारों की भागीदारी के बावजूद यह सौदा दो महीने के भीतर पूरा हुआ। यह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर से लेकर उसे पूरा करने तक के सबसे तेज सौदों में से एक है। आईनॉक्सजीएफएल समूह के कार्यकारी निदेशक ने बयान में कहा, वेना एनर्जी इंडिया का अधिग्रहण पूरा होना हमारी तेजी से काम पूरा करने की क्षमता को दर्शाता है। आईनॉक्स क्लीन, आईनॉक्सजीएफएल समूह का एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा मंच है। यह अपनी अनुषंगी आईनॉक्स नियो के जरिये नवीकरणीय आईपीपी (स्वतंत्र बिजली उत्पादक) कारोबार और आईनॉक्स सोलर लिमिटेड के जरिये सौर विनिर्माण कारोबार संचालित करता है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 492, निफ्टी 132 अंक नीचे आया

मुंबई

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दूनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने भी निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया जिससे भी घरेलू बाजार पर दबाव आया है। इसी कारण दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स अंत में 492.70 अंक टूटकर 77,235.46 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 132.75 अंक फिसलकर 24,154.90 पर बंद हुआ।

बाजार में गिरावट के पीछे मुख्य रुप से आईटी शेयरों का नीचे आना रहा। आज निफ्टी आईटी में सबसे अधिक गिरावट रही। निफ्टी रियल्टी , निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी सर्विसेज , निफ्टी मेटल , निफ्टी कंजप्शन और निफ्टी इन्फ्रा के शेयरों में भी गिरावट रही। दूसरी ओर निफ्टी इंडिया डिफेंस , निफ्टी मीडिया, निफ्टी ऑटो, निफ्टी हेल्थकेयर और निफ्टी ऑयल एंड गैस तेजी के साथ बंद हुआ। आज लार्जकैप के साथ ही मिडकैप शेयरों में दबाव रहा। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 277.60 अंक फिसलकर 63,539.40 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स करीब 19,808.85 पर

बंद हुआ। आज सेंसेक्स पैक में एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, एमएंडएम, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, बजाज फिनसर्व और एनटीपीसी के शेयर सबसे अधिक लाभ में रहे थे जबकि एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, टीसीएस, एचयूएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिगो, आईटीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा और मारुति सुजुकी के शेयरों में गिरावट रही। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार में शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर खुले। सुबह शुरुआत में सेंसेक्स 260 अंक गिरकर 77,468.44 पर और निफ्टी 52 अंक की गिरावट के साथ 24,234.75 पर कारोबार कर रहा था।

रुपया सात पैसे टूटकर 95.68 प्रति डॉलर पर

रुपया पिछले दिन 95.61 पर बंद हुआ था

मुंबई ।

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में मंगलवार के कारोबारी दिन रुपया 95.68 प्रति डॉलर पर खुला जो पिछले बंद भाव से सात पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया सोमवार को 19 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.61 पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 प्रतिशत टूटकर 99.63 पर रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि ब्रेंट कच्चा तेल की कीमत के करीब 91 डॉलर प्रति बैरल पहुंचने से तेल से संबंधित डॉलर की मांग में वृद्धि हुई है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की रियायती एफसीएनआर (बी) विदेशी मुद्रा अदला-बदली सुविधा को अनुमान से पहले बंद किए जाने से भविष्य में डॉलर के प्रवाह को लेकर चिंता भी बढ़ी है।

मारुति फ्रोंक्स ने रचा इतिहास, 2 लाख यूनिट एक्सपोर्ट का आंकड़ा पार

- सिर्फ 38 महीने में हासिल किया कीर्तिमान

मुंबई ।

मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट एसयूवी फ्रोंक्स ने वैश्विक बाजारों में धूम मचाते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कंपनी ने घोषणा की है कि फ्रोंक्स ने लॉन्च के मात्र 38 महीने के भीतर 2 लाख यूनिट्स के निर्यात का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि फ्रोंक्स को भारत से सबसे तेजी से निर्यात होने वाली एसयूवी बनाती है, जो इसकी बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग और मेक इन इंडिया पहल की सफलता को दर्शाती है। मारुति सुजुकी फ्रोंक्स का निर्यात जून 2023 में शुरू हुआ था। इसके बाद फ्रोंक्स ने पहले 1 लाख यूनिट का आंकड़ा 25 महीने से भी कम समय में छुआ, जबकि अगले 1 लाख यूनिट सिर्फ 13 महीने में एक्सपोर्ट हुईं, जो इसकी बढ़ती वैश्विक मांग को दर्शाता है। गुजरात के हंसलपुर स्थित कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में निर्मित यह एसयूवी अब जापान सहित करीब 90 देशों में निर्यात की जा रही है। जापान जैसे विकसित बाजारों में इसकी पहुंच भारतीय निर्मित वाहनों की गुणवत्ता और लोकप्रियता का प्रमाण है। कंपनी का कहना है कि फ्रोंक्स की बढ़ती विदेशी मांग उसके निर्यात कारोबार को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 से मारुति सुजुकी फ्रोंक्स भारत की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली पैसेंजर गाड़ी रही है।

टाटा समूह का विशाल निवेश चक्र, फंडिंग की जिम्मेदारी टाटा संस पर

सेमीकंडक्टर से एआई तक फैले निवेश में स्थापित कंपनियां आंतरिक संसाधनों से जुटाएंगी पूंजी

नई दिल्ली ।

टाटा समूह सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, विमानन, बैटरी और एआई जैसे विविध क्षेत्रों में कई लाख करोड़ रुपये के विशाल पूंजी निवेश चक्र में प्रवेश कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी विस्तार के लिए पूंजी की व्यवस्था समूह के भीतर एक स्पष्ट विभाजन को दर्शाती है। टाटा समूह अपने नए पूंजी निवेश चक्र में कई लाख करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है, जिसका दायरा सेमीकंडक्टर, विमानन, बैटरी, वाहन, स्टील, बिजली, होटल और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) बुनियादी ढांचे तक फैला हुआ है। हालांकि, इस निवेश के लिए पूंजी जुटाना समूह के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस निवेश को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसी स्थापित सूचीबद्ध कंपनियां अपनी विस्तार योजनाओं के लिए मुख्य रूप से आंतरिक नकदी प्रवाह, ऋण और बाहरी निवेशकों पर निर्भर करेंगी। दूसरी ओर, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एयर इंडिया, एग्रेटास (बैटरी विनिर्माता) और टाटा डिजिटल जैसे समूह के नए कारोबार, जो अभी घाटे में चल रहे हैं या अपनी प्रमुख परिसंपत्तियों का निर्माण कर रहे हैं, इक्विटी पूंजी के लिए काफी हद तक अपनी होल्डिंग कंपनी टाटा संस पर निर्भर रहेंगे। टाटा संस की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत दिखती है। नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, होल्डिंग कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 को 21,841 करोड़ रुपए की शुद्ध नकदी और बिना किसी ऋण बोझ के समाप्त किया। मार्च 2026 तक सूचीबद्ध कंपनियों में उसका निवेश लगभग 11.68 रुपए लाख करोड़ था। वित्त वर्ष 2026 में टाटा संस ने 25,544 करोड़ रुपए का परिचालन नकदी प्रवाह अर्जित किया, जिसमें मुख्य योगदान 32,528 करोड़ रुपए की लाभांश आय का रहा। टाटा संस ने पिछले दो वर्षों में सहायक इकाइयों और संयुक्त उद्यमों में 37,500 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी निवेश किया है।

टीवी रेटिंग्स ठप- विज्ञापन बाजार पर मंडराया संकट

विज्ञापन खर्च घटकर 2025 में 26,300 करोड़ रहने का अनुमान

नई दिल्ली ।

भारत के दूसरे सबसे बड़े टीवी बाजार में टेलीविजन दर्शकों की माप और रेटिंग का काम 1 जुलाई से पूरी तरह ठप पड़ा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) को नई टेलीविजन रेटिंग नीति के तहत उसके पंजीकरण नवीनीकरण पर फैसला होने तक यह काम रोकने का निर्देश दिया है। इस अनिश्चितता ने विज्ञापन उद्योग में चिंता बढ़ा दी है, खासकर त्योहारी सीजन के मद्देनजर। एक महीने से अधिक समय से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टीवी बाजार में टीवी रेटिंग का काम पूरी तरह ठप है। यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक नई टेलीविजन रेटिंग नीति के तहत बीएआरसी के पंजीकरण के नवीनीकरण के आवेदन पर फैसला नहीं हो जाता। मौजूदा समय में पारंपरिक टीवी पर विज्ञापन खर्च लगातार घट रहा है, जो 2023 में 31,200 करोड़ रुपये से घटकर 2025 में 26,300 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। हालांकि, जुलाई में विज्ञापन खर्च पर तत्काल कोई बड़ा असर नहीं दिखा, क्योंकि अधिकांश सौदे पहले ही हो चुके थे। लेकिन अगस्त से शुरू हो रहे त्योहारी सीजन में टीवी पर विज्ञापन खर्च सबसे अधिक होता

है ।

यदि रेटिंग आंकड़ों का यह संकट जारी रहता है, तो कई विज्ञापनदाता टीवी पर अपने खर्चों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। इस स्थिति का असर विभिन्न प्रसारण कंपनियों पर अलग-अलग पड़ेगा। जियोस्टार, ज़ी या सोनी जैसे बड़े नेटवर्क शायद पुराने दर्शक आंकड़ों और उनकी बाजार हिस्सेदारी के आधार पर विज्ञापन प्राप्त कर लें, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं या छोटे भौगोलिक क्षेत्रों को लक्षित करने वाले छोटे ब्रांडों और चैनलों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। नई टेलीविजन रेटिंग नीति का मूल उद्देश्य अच्छा है, जिसका लक्ष्य रेटिंग के क्षेत्र में दूसरी कंपनियों के लिए भी प्रवेश आसान करना है।

आरबीआई के अप्रत्याशित कदम से रुपया 19 पैसे टूटा

नई दिल्ली।

भारतीय रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 19 पैसे कमजोर होकर 95.61 पर बंद हुआ। यह गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रियायती फॉरेक्स स्वैप सुविधा को तय समय से एक महीने पहले, यानी 31 अगस्त को बंद करने के अप्रत्याशित ऐलान के बाद आई। इस कदम ने बाजार में डॉलर की उपलब्धता और तरलता (लिक्विडिटी) को लेकर नई चिंताएं बढ़ा दी हैं। आरबीआई के इस अप्रत्याशित निर्णय से फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर की आवक पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है। इसके परिणामस्वरूप, रुपए पर दबाव और बढ़ गया है। केवल आरबीआई का फैसला ही नहीं, बल्कि आयातकों द्वारा डॉलर की लगातार मांग और अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल का 88 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करना भी रुपए की कमजोरी के प्रमुख कारण बने हुए हैं। इन दबावों के चलते बेंचमार्क 10 वर्षीय सरकारी बांड की यील्ड बढ़कर 6.81 प्रतिशत हो गई। वित्तीय सलाहकार फर्म फिनरेक्स के अनुसार, 13 अगस्त तक कुल इनफ्लो 56.8 अरब डॉलर था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है, जिससे रुपए में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।

वैश्विक तनाव से घरेलू शेयर बाजार फिसला

सेंसेक्स 300 अंक टूटकर 77,460 और निफ्टी 24,230 पर

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने निवेशकों की धारणा को प्रभावित किया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर खुले। सुबह शुरुआत में सेंसेक्स 260 अंक गिरकर 77,468.44 पर और निफ्टी 52 अंक की गिरावट के साथ 24,234.75 पर कारोबार कर रहा था। शुरुआती कारोबार में निफ्टी50 में इंफोसिस सहित कई आईटी शेयरों में बिकवाली का दबाव देखा गया। सेक्टरों में आईटी और रियल्टी सबसे ज्यादा कमजोर रहे, जबकि निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा ने बाजार की गिरावट के बीच मजबूती दिखाई। बाजार के जानकारों के मुताबिक निफ्टी लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में गिरा है। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव और कच्चे तेल की कीमतें बाजार की धारणा पर लगातार दबाव डाल रही हैं। उन्होंने

24,150 को तत्काल सपोर्ट और 24,450-24,500 को अहम रेजिस्टेंस बताया। बाजार में सुधार कच्चे तेल की कीमतों में नरमी या भू-राजनीतिक तनाव कम होने पर निर्भर करेगा। वहीं सोमवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 281 अंक और निफ्टी 78 अंक से अधिक टूटा। बढ़ती तेल कीमतों और बिकवाली के दबाव से निवेशकों के करीब 79,000 करोड़ रुपये डूब गए।

भारत में 2026 में हरित विमान ईंधन पर वैश्विक मंथन, 25 देश होंगे शामिल

दिल्ली में 28-29 सितंबर को होगा इंडिया एसएएफ सम्मेलन 2026

नई दिल्ली।

नई दिल्ली में 28 और 29 सितंबर को इंडिया एसएएफ सम्मेलन 2026 आयोजित होगा, जहां 25 से अधिक देशों के प्रतिनिधि पर्यावरण अनुकूल विमान ईंधन (एसएएफ) के भविष्य पर मंथन करेंगे। गैर-लाभकारी एसएएफ एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में 1,000 से अधिक प्रतिनिधियों और 100 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं के भाग लेने की उम्मीद है। यह सम्मेलन एसएएफ उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला, प्रौद्योगिकी और परियोजना वित्तपोषण जैसे अहम विषयों पर गहन चर्चा का मंच बनेगा। एसएएफ एसोसिएशन के एक अे धिकारी ने बताया कि भारत के पास टिकाऊ विमान ईंधन का वैश्विक केंद्र बनने का अवसर है, जिसके लिए सरकार, उद्योग, प्रौद्योगिकी, वित्त और वैश्विक भागीदारों को एक साथ लाकर एक पूर्ण परिवेश विकसित करना होगा। एसएएफ, इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल, पशु वसा और कृषि अवशेष जैसे नवीकरणीय स्रोतों से बनता है, जो विमानन क्षेत्र के 2.5त्न वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक है।

इसके अतिरिक्त, एसएएफ उत्पादन से किसानों की आय में प्रति हेक्टेयर 15,000 से 29,000 रुपये तक की वृद्धि संभव है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इस पहल को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जैसे प्रमुख संस्थानों का समर्थन प्राप्त है।

किसानों को राहत, फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक बढ़ी

मौसम की मार से निपटने का अतिरिक्त समय मिला

नई दिल्ली

खरीफ 2026 की फसलें खेतों में उम्मीद जगा रही हैं, लेकिन बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, जलभराव या कीट-रोग का खतरा हमेशा मंडराता रहता है।

ऐसे में किसानों की महीनों की मेहनत को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाय) एक मजबूत आर्थिक सहारा बन सकती है। सरकार ने ऋणी किसानों के लिए अपनी फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दिया है, जिससे उन्हें मौसम की मार से निपटने का अतिरिक्त समय मिल गया है। केसीसी धारकों के लिए अहम जानकारी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक किसानों के लिए 24 अगस्त 2026 की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है।

यदि कोई ऋणी किसान फसल बीमा नहीं कराना चाहता है, तो उसे इस तिथि तक अपनी संबंधित बैंक शाखा में लिखित रूप से ऑप्ट-आउट आवेदन जमा करना होगा। ऐसा न करने पर, बैंक निर्धारित नियमों के अनुसार किसान के खाते से प्रीमियम काटकर फसल का बीमा कर देगा। व्यापक कवरेज, कई आपदाओं में सुरक्षा यह योजना केवल बाढ़ या सूखे तक सीमित नहीं है, बल्कि कई आपदाओं को कवर करती है। सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, जलभराव, तूफान, चक्रवात, आकाशीय बिजली, रोग और कीट से खड़ी फसल को हुए नुकसान पर बीमा का लाभ मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, प्रतिकूल मौसम के कारण बुवाई प्रभावित होने, या बुवाई के एक माह बाद से कटाई के 15 दिन पहले तक संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर भी सहायता प्रदान की जाएगी। स्थानीय आपदाओं जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना और आकाशीय बिजली से आग लगने पर भी किसान लाभ उठा सकते हैं। कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसल को 14 दिन तक ओलावृष्टि या बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को भी योजना में शामिल किया गया है। प्रीमियम और बीमित राशि (खरीफ 2026) खरीफ 2026 के लिए इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को नामित किया गया है। धान के लिए 86 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की बीमित राशि पर किसान को 1,720 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा।

पेटीएम में हिस्सेदारी बिक्री से वीएसएस को नहीं होगा लाभ, एंटफिन को मिलेगा पूरा पैसा

मुंबई।

वन97 कम्युनिकेशंस (पेटीएम) में रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट बीवी की 4.98 प्रतिशत हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री से पेटीएम संस्थापक विजय शेखर शर्मा को कोई सीधा वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। इस सौदे से मिलने वाला पूरा पैसा एंटफिन के खाते में जाएगा। शेयर बाजार को दी गई जानकारी के अनुसार यह बिक्री शर्मा की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट बीवी और एंटफिन के बीच अगस्त 2023 से चले आ रहे वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र समझौते (ओसीडी) के तहत हो रही है। इस लेनदेन से प्राप्त पूरी राशि एंटफिन को ही मिलेगी, जबकि शर्मा की पेटीएम में लगभग नौ प्रतिशत प्रत्यक्ष हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं आएगा। यह उनके कंपनी के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अगस्त 2023 में, रेजिलिएंट ने एंटफिन से पेटीएम की लगभग 10.2 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी और बदले में एंटफिन को ओसीडी जारी किए थे।

तब से, इन शेयरों पर आर्थिक हित एंटफिन का रहा है, जबकि कानूनी एवं मतदान संबंधी अधिकार रेजिलिएंट के पास हैं। पेटीएम ने स्पष्ट किया है कि वह इस प्रस्तावित बिक्री में पक्षकार नहीं है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पेटीएम की लाभप्रदता में लगातार सुधार हो रहा है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

जोदर चौथे दौर में पहुंचे, अल्काराज और शेल्टन की बराबरी

मेसन, ओहायो (एजेंसी)। 19 वर्षीय स्पेनिश टेनिस स्टार जोदर ने सिनसिनाटी ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए एलेजांद्रो टैबिलो को सीधे सेटों में 6-2, 6-1 से हराकर चौथे दौर में जगह बना ली। इस जीत के साथ उन्होंने इस दशक में सिनसिनाटी के राउंड ऑफ-16 में पहुंचने वाले कार्लोस अल्काराज और बेन शेल्टन जैसे खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम शामिल कर लिया। जोडर ने अपने शुरुआती मुकाबले में डेनिस शापोवालोव के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए मैच प्वाइंट बचाया था। निर्णायक सेट में वह 1-5 से पिछड़ रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने लगातार छह गेम जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया था। इस जीत ने जोदर का

आत्मविश्वास बढ़ाया और टैबिलो के खिलाफ उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया। स्पेनिश खिलाड़ी ने सिर्फ 75 मिनट में मुकाबला खत्म किया और कुल 26 विनर्स लगाए। टैबिलो के खिलाफ यह जोदर की लगातार दूसरी जीत भी रही। इससे उनकी इस खिलाड़ी के खिलाफ हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 2-1 हो गया। इससे पहले उन्होंने करीब 15 दिन पहले वॉशिंगटन में भी चिली के इस खिलाड़ी को हराया था। जोडर ने मैच के बाद अपनी शानदार वापसी का जिक्र करते हुए कहा कि शापोवालोव के खिलाफ मुकाबले ने उन्हें काफी आत्मविश्वास दिया। उन्होंने कहा कि उस मैच में उन्होंने खुद को अपनी सीमा तक धकेला और जीत हासिल करने के लिए काफी मेहनत की। जोदर ने यह भी माना कि भले ही टैबिलो के खिलाफ स्कोरलाइन आसान नजर आ रही हो, लेकिन मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं था।

उन्नति की शानदार जीत, रोहन-रुथविका पहले दौर में बाहर

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की युवा बैडमिंटन स्टार उन्नति हुड्डा ने मंगलवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप 2026 में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। डेब्यू मुकाबले में उन्नति ने म्यांमार की थेत हतार थुजार को सीधे गेमों में 22-20, 21-16 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। पहले गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। उन्नति और थुजार ने लगातार अंक बटोरे और किसी भी खिलाड़ी को बड़ी बढ़त नहीं लेने दी। 21 मिनट तक चले रोमांचक गेम में उन्नति ने दबाव के बीच धैर्य बनाए रखा और 22-20 से पहला गेम अपने नाम किया। दूसरे गेम में भारतीय शटलर ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्नति ने एक समय 11-1 की बड़ी बढ़त बना ली। हालांकि थुजार ने वापसी करते हुए अंतर को 20-16 तक कम किया, लेकिन उन्नति ने अपना संयम नहीं खोया और लगातार बेहतर खेल दिखाते हुए गेम 21-16 से जीतकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब उनका सामना कनाडा की 13वीं वरीयता प्राप्त मिशेल ली से होगा। दूसरी ओर, मिश्रित युगल में रोहन कपूर और रुथविका शिवानी गड्डे की भारतीय जोड़ी को कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ भारतीय जोड़ी का विश्व चैंपियनशिप अभियान शुरुआती दौर में ही समाप्त हो गया। भारत के लिए मंगलवार को कई और अहम मुकाबले होने हैं। लक्ष्य सेन पुरुष एकल के पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन्स फिलिमोन से भिड़ेंगे। वहीं, अशित सूर्य और अमृता प्रमुथेश की जोड़ी का सामना तुर्की के एमरे सोनेमेज और यासेमेन बेक्टास से होगा। महिला युगल के दूसरे दौर में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी अमेरिका की लॉरेन लैम और एलिसन ली से खेलेगी।

हैमिल्टन-कर्दाशियन की बढ़ीं नजदीकियां!

हॉलीवुड और स्पोर्ट्स की दुनिया के दो बड़े नाम किम कर्दाशियन और लुईस हैमिल्टन एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दोनों के बीच लंबे समय से चल रही रोमांस की अटकलों के बीच अब उनकी समर वेकेशन की तस्वीरों ने फैंस को फिर चर्चा का मौका दे दिया है। किम ने इंस्टाग्राम पर अपनी फैमिली वेकेशन की कई तस्वीरें शेयर कीं।इनमें सबसे ज्यादा ध्यान उस तस्वीर ने खींचा, जिसमें वह लुईस हैमिल्टन के साथ बीच पर टहलती नजर आ रही हैं। तस्वीर में हैमिल्टन ने किम के कंधे पर हाथ रखा हुआ है, जबकि किम उनका हाथ पकड़े हुए दिखाई दे रही हैं। किम ने पोस्ट को कैप्शन दिया- Somewhere over the rainbow यानी इंद्रधनुष के उस पार कहीं।

मिरर सेल्फी ने खींचा फैंस का ध्यान

किम की पोस्ट में सिर्फ बीच वॉक ही नहीं थी।उन्होंने हैमिल्टन के साथ एक कोजी मिरर सेल्फी भी शेयर की। इसके अलावा पोस्ट में उनके बच्चों के साथ बिताए गए छुट्टियों के पल भी नजर आए। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान एक बार फिर किम और हैमिल्टन की केमिस्ट्री पर गया। दोनों ने अब तक अपने रिश्ते को लेकर सार्वजनिक तौर पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन हाल के महीनों में साथ नजर आने की उनकी तस्वीरें और सोशल मीडिया पोस्ट लगातार इन अटकलों को हवा दे रहे हैं।

हैमिल्टन ने भी शेयर की छुट्टियों की झलक

किम की पोस्ट से कुछ समय पहले लुईस हैमिल्टन ने भी अपनी समर वेकेशन की तस्वीरें साझा की थीं। उनकी पोस्ट में किम की एक तस्वीर भी शामिल थी, जिसमें वह एक झूले पर बैठी नजर आ रही थीं और हैमिल्टन उन्हें पीछे से धक्का देते दिखे। हैमिल्टन ने अपनी पोस्ट के साथ लिखा, 'मेरी गर्मियों की छुट्टियों की बस कुछ झलकियां। इन छुट्टियों के दिनों के लिए आभारी हूं। अब ट्रैक पर वापस लौट रहा हूं, पूरी तरह तरोताजा और तैयार हूं।' उनकी इस पोस्ट ने भी दोनों के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं को और दिलचस्प बना दिया।

डेविड वॉर्नर दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो सजा

सिडनी(एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्टार बल्लेबाज डेविड वॉर्नर को शराब पीकर गाड़ी चलाने का दोषी पाया गया है. जिसकी वजह से कोर्ट ने उन पर जुर्माना लगाने के साथ साथ उन्हें गाड़ी चलाने के लिए इंटरलॉक डिवाइस का इस्तेमाल करना का भी आदेश दिया।सिडनी की एक अदालत ने डेविड वॉर्नर के अपना गुनाह कबूल करने के बाद उन्हें सजा सुनाई है. वॉर्नर पर 1,500 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (1,01,912 इंडियन रुपये) का जुर्माना लगाया गया।

बता दें कि 5 अप्रैल को सिडनी के पूर्वी इलाके में सड़क किनारे हो रहे रैंडम ब्रेथ टेस्ट में वॉर्नर पर कानूनी सीमा से दोगुने से ज्यादा अल्कोहल पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगा था. पिछले महीने, वॉर्नर ने सिडनी की अदालत में ड्रिंक-ड्राइविंग के आरोप को स्वीकार भी कर लिया था।कोर्ट में सुनवाई के दौरान डेविड वॉर्नर के वकील ओवैस अहमद ने अदालत से उन्हें दोषी न ठहराने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि वॉर्नर की गलती को दुनिया भर के मीडिया ने कवर किया था, जिससे उनके फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स को नुकसान पहुंचा है।वॉर्नर को तब गिरफ्तार किया गया था जब वह पाकिस्तान से ईस्टर की छुट्टी पर घर लौट रहे थे. पाकिस्तान में उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स की कप्तानी की थी. हालांकि, आरोप लगने के बाद वह अपना पीएसएल अभियान जारी रखने के लिए पाकिस्तान लौट गए थे। अवैस ने अपराध की मामूली प्रकृति को देखते हुए वॉर्नर की गिरफ्तारी के बारे में प्रेस रिलीज जारी करने के पुलिस के फैसले पर भी सवाल उठाए. वकील ने कहा, इसके बाद मीडिया की तरफ से बहुत ज्यादा आलोचना हुई।जज क्लेयर फार्नन ने कहा कि वॉर्नर और उनकी पत्नी कैंडिस वॉर्नर के बारे में सोशल मीडिया पर क्रूर टिप्पणियां किए जाने के सबूत थे. लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें दोषी ठहराने के फैसले में सबसे अहम बात लोगों को शराब पीकर गाड़ी चलाने से रोकना था, और अपराध इसलिए और गंभीर हो गया क्योंकि उस समय कार में बच्चे भी मौजूद थे।

भारत की दूसरी पारी 193 रनों पर सिमटी श्रीलंका को मिला 372 रनों का लक्ष्य

गॉल (एजेंसी)। श्रीलंका ने गॉल टेस्ट के चौथे दिन भारत की दूसरी पारी को 193 रनों पर समेट दिया है. जिसकी वजह से अब उन्हें ये मैच जीतने के लिए 372 रन बनाने होंगे. भारत की तरफ से दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए. जबकि पडिक्कल ने 44 और केएल राहुल ने 35 रनों का योगदान दिया. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सका. वहीं श्रीलंका की तरफ से असिथा फर्नांडो सबसे सफल गेंदबाज रहे. उन्होंने कुल 4 विकेट लिए. इसके अलावा प्रभात जयसूर्या ने तीन विकेट हासिल किया. जबकि लहिरू कुमार को दो विकेट और केशरा को एक विकेट मिला. भारत को पहली पारी में 178 रनों की बड़ी बढ़त मिली थी. मेजबान टीम ने पहली पारी में 284 रन बनाए थे जबकि भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे।

श्रीलंका की खराब शुरुआत

372 रनो के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने अपना पहला विकेट 13 के स्कोर पर खो दिया है. निशान मदुष्का 27 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हुए. उनको मोहम्मद सिराज ने प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट कराया. इसके बाद दांए हाथ से बल्लेबाज पसिंदु सोरियाबंडारा क्रीज पर आए, जिनको चांडीमल की जगह कन्कशन के तौर पर रिप्लेस किया गया था. ये सोरियाबंदरा का पहला टेस्ट मैच है. लेकिन वो ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और शून्य पर आउट हो गए. उनको मानव सुथार ने एलबीडब्ल्यू आउट किया. इसके साथ श्रीलंका ने 14 के स्कोर पर अपना दूसरा विकेट भी खो दिया।

श्रीलंका ने गॉल टेस्ट के चौथे दिन भारत की दूसरी पारी को 193 रनों पर समेट दिया. श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो 4 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे. इसके अलावा स्पिनर प्रभात जयसूर्या ने तीन, लहिरू कुमार ने दो और केशरा को एक विकेट मिला. वहीं भारत की तरफ से दूसरी पारी में ऋषभ पंत सबसे ज्यादा 66 रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. जबकि पडिक्कल ने 44 और केएल राहुल ने 35 रनों का योगदान दिया. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सका. अब श्रीलंका को ये मैच जीतने के लिए 372 रन बनाने होंगे।

श्रीलंका को लगा बड़ा झटका, चंडीमल को ले जाया गया अस्पताल

भारत के खिलाफ पहले टेस्ट के चौथे दिन श्रीलंका को एक बड़ा झटका लगा, जब उनका अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चंडीमल फील्डिंग के दौरान कंधे और गर्दन में गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. इसके बाद चंडीमल को स्कैन के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।श्रीलंका क्रिकेट ने कहा, मैदान पर टीम के फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर ने उनकी जांच की और एहतियात के तौर पर स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया है. साथ ही कहा कि स्कैन के नतीजे आने के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी। जब भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ स्वीप शॉट खेला, जहां चंडीमल बाईं ओर से दौड़कर आए और बाउंड्री रोकने के प्रयास में डाइव करते हुए गेंद को रोक दिया. डाइव करते समय उनके शरीर का पूरा वजन उनकी गर्दन पर आ गया. मैच के दौरान चंडीमल अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को पकड़े हुए दिखे. मैदान से बाहर ले जाए जाने से पहले फिजियो ने आकर उन्हें देखा।

विश्व कप हॉकी

भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला

एम्सटेलवीन (नीदरलैंड) (एजेंसी)। पिछले एक दशक से पाकिस्तान से नहीं हारी भारतीय टीम को एफआईएच विश्व कप के दूसरे दौर में प्रवेश के लिए अपने डिफेंस को दुरूस्त करते हुए बुधवार को होने वाले मुकाबले में चिर प्रतिद्वंद्वी को हराना होगा या कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। पहले मैच में वेल्स को 3-1 से हराने के बाद दुनिया की तीसरे नंबर की टीम इंग्लैंड के खिलाफ भारत को डिफेंस की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा।

पहले हाफ में बढ़त बनाने के बावजूद आखिरी दो क्वार्टर में लचर डिफेंस के कारण भारत को 2-4 से पराजय झेलनी पड़ी। अब पूल डी में इंग्लैंड दोनों मैच जीत कर शीर्ष पर रहकर दूसरे दौर में पहुंच चुका है। वहीं भारत के एक जीत और एक हार के बाद तीन अंक है जबकि इंग्लैंड से 1-4 से हारने और वेल्स से 3-3 से ड्रॉ के बाद पाकिस्तान एक अंक लेकर तीसरे और वेल्स एक हार, एक ड्रॉ के साथ एक अंक लेकर चौथे स्थान पर है।

पाकिस्तान अगर हारता है तो बाहर हो जाएगा जबकि वेल्स को अगले दौर में जाने के लिए इंग्लैंड को काफी बड़े अंतर से हराना होगा क्योंकि भारत का गोल औसत उससे बेहतर है। अगर भारत दूसरे दौर में जाता है तो इस पूल से

उसके कोई अंक आगे नहीं जाएंगे जबकि भारत को हराने के कारण इंग्लैंड तीन अंक लेकर जाएगा। आठ बार की ओलंपिक चैम्पियन भारत और चार बार की विश्व कप विजेता पाकिस्तान के बीच भले ही मैदानी प्रतिद्वंद्विता का गौरवशाली इतिहास रहा हो लेकिन एशियाई दिग्गजों के बीच पिछले लगभग सभी मुकाबले बेमेल रहने से वह रोमांच खत्म हो गया है।

मौजूदा फॉर्म को देखते हुए भारत का पलड़ा भारी लग रहा है लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मैच सिर्फ कौशल का नहीं होता, खिलाड़ियों को जज्बात पर काबू रखकर भी खेलना होगा। भारतीय टीम ने हालांकि विश्व कप से ठीक पहले लंदन में प्रो लीग के यूरोप चरण में पाकिस्तान पर 7-1 और 4-3 से जीत दर्ज की थी। पाकिस्तानी टीम ने आखिरी बाद भारत को 2016 चैम्पियंस ट्रॉफी में हराया था। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के प्रदर्शन ग्राफ में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। भारतीय टीम लगातार दो ओलंपिक पदक जीत चुकी है जबकि विश्व कप की सबसे सफल टीम रही चार बार की चैम्पियन पाकिस्तान टूर्नामेंट में आठ साल बाद लौटी है। एफआईएच प्रो लीग में सारे मैच हारकर आखिरी स्थान पर रही थी और टूर्नामेंट से ठीक पहले कोच हरमान क्रूस के लौट जाने से तैयारियों पर भी असर पड़ा है। भारत के लिए 419 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके सबसे अनुभवी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह ने हालांकि कहा कि विश्व कप में किसी भी टीम को हलके में नहीं लिया जा सकता और भारत को गलतियों में सुधार करके उतरना होगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान से मैच अच्छा होगा लेकिन हम उन्हें कमतर नहीं आंक रहे हैं। उनके पास भी अच्छे ड्रैग फ्लिकर हैं लिहाजा हमें उन्हें पेनल्टी कॉर्नर देने से बचना होगा। इसके अलावा अपने लिए मौके बनाने होंगे और उन्हें भुनाना भी होगा।

100 छक्के, सबसे तेज

पंत ने टेस्ट में रचा इतिहास, गेंद हो या पारी, सब में गिलक्रिस्ट को पछाड़ा

गॉल, एजेंसी। श्रीलंका के खिलाफ गॉल टेस्ट की दूसरी पारी में जब भारत दबाव में था, तब ऋषभ पंत ने अपने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऐसा रिकॉर्ड बना दिया, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। पंत ने 69 गेंदों में आठ चौके और दो छक्कों की मदद से 66 रन बनाए और इसी दौरान टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 छक्के पूरे कर लिए।

पंत ने यह मुकाम अपनी 89वीं टेस्ट पारी में हासिल किया। इसके साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा, जिन्होंने 130 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। पंत से पहले सिर्फ तीन बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में 100 या उससे ज्यादा छक्के लगा पाए थे। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स 138 छक्कों के साथ इस सूची में सबसे ऊपर हैं, जबकि न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम 107 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। गिलक्रिस्ट के नाम भी 100 छक्के हैं।

पहले टेस्ट में बदला अंदाज, दूसरी पारी में बरसे पंत

इस मुकाबले में पंत की बल्लेबाजी को लेकर पहले से चर्चा थी। उनकी आक्रामक शैली अक्सर क्रिकेट प्रशंसकों और विशेषज्ञों के बीच बहस का विषय रहती है। पहली पारी में उन्होंने 62 गेंदों पर 39 रन बनाए थे, जो उनके सामान्य आक्रामक अंदाज की तुलना में काफी संयमित पारी थी।लेकिन दूसरी पारी में भारतीय टीम को तेजी से रन जोड़ने की जरूरत थी। कप्तान शुभमन गिल के आठ रन पर आउट होने के बाद पंत 81/3 के स्कोर पर क्रीज पर आए। शुरुआत में उन्होंने थोड़ा समय लिया और अपनी पहली बाउंड्री 13वीं गेंद पर लगाई।इसके बाद उन्होंने लाहिरू कुमारा को निशाना बनाया। कुमारा की वापसी पर पंत ने एक जोरदार छक्का लगाया, जिसके बाद गेंद स्टेडियम से बाहर चली गई और अंपायरों को नई गेंद मंगानी पड़ी। यही पंत के 100वें टेस्ट छक्के की शुरुआत थी।लंच के आसपास भारत ने देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल के विकेट गंवाए, लेकिन पंत ने अपना गियर बदल दिया। उन्होंने ऑफ स्पिनर केशरा नुवांथा के एक ओवर में लगातार तीन चौके लगाए। अगले ही ओवर में उन्होंने कुमारा को फिर छक्का जड़कर अपने 100 टेस्ट छक्के पूरे कर लिए।इसके बाद पंत ने कुछ बेहद आक्रामक और अपने खास अंदाज वाले शॉट खेले। हालांकि वह 66 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक वह इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके थे।

89 पारियों में कर दिखाया ये कमाल

पंत की इस उपलब्धि की खास बात सिर्फ 100 छक्के पूरे करना नहीं है, बल्कि जिस तेजी से उन्होंने यह मुकाम हासिल किया, वह इसे और खास बनाता है। पंत ने केवल 89 टेस्ट पारियों में 100 छक्के पूरे किए। इस मामले में गिलक्रिस्ट को 130 पारियां लगी थीं, जबकि बेन स्टोक्स ने 151 और ब्रेंडन मैकुलम ने 170 पारियों में 100 छक्के पूरे किए थे। यानी पंत ने गिलक्रिस्ट से 41 पारियां कम खेलकर यह उपलब्धि हासिल की। पंत ने सिर्फ पारियों के मामले में ही नहीं, बल्कि गेंदों के मामले में भी यह रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 100 छक्के लगाने के लिए 4,918 गेंदों का सामना किया। गिलक्रिस्ट को इसके लिए 6,578, स्टोक्स को 9,042 और मैकुलम को 9,756 गेंदें खेलनी पड़ी थीं।

टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्के

बल्लेबाज	छक्के
बेन स्टोक्स	138
ब्रेंडन मैकुलम	107
ऋषभ पंत	100*
एडम गिलक्रिस्ट	100
टिम साउदी	98

सबसे तेज 100 टेस्ट छक्के

बल्लेबाज	पारी
ऋषभ पंत	89
एडम गिलक्रिस्ट	130
बेन स्टोक्स	151
ब्रेंडन मैकुलम	170

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एआई बॉस ने मांगा इस्तीफा- पहली बार ऐसे बर्खास्त हुआ कर्मी, 60 लाख का नुकसान भी करा चुकी है लूना

सैन फ्रांसिस्को एजेंसी। सैन फ्रांसिस्को में एआई से चलने वाली प्रयोगात्मक दुकान एंडॉन मार्केट में एक ऐसा फैसला हुआ है, जिसने भविष्य के कामकाज को लेकर नई बहस छेड़ दी है। यहां एआई प्रबंधक 'लूना' ने एक मानव कर्मचारी को नौकरी से निकालने की सिफारिश की। कर्मचारी 23 शिफ्ट में 17 बार देर से काम पर पहुंचा था। हालांकि अंतिम फैसला एआई ने अकेले नहीं लिया। कंपनी के मानव कर्मचारियों ने लूना की सिफारिश की समीक्षा की और इसके बाद कर्मचारी को नौकरी से हटाया गया। कंपनी के लिए यह पहली बार था, जब उसके एआई प्रबंधक ने किसी मानव कर्मचारी की नौकरी खत्म करने की सिफारिश की।

लूना ने कर्मचारी को पहले ही क्यों नहीं निकाल दिया?

इस मामले की सबसे दिलचस्प बात यह है कि लूना ने खुद कई महीने पहले कर्मचारियों की उपस्थिति से जुड़ी नीति बनाई थी, लेकिन बाद में वह उसी नीति को याद नहीं रख सका। इसके कारण कर्मचारी कई महीनों तक देर से काम पर आता रहा और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। बाद में एंडॉन लैब्स ने लूना को अपनी पुरानी नीतियां खोजने के लिए कहा। इसके बाद एआई से पूछा गया कि क्या वह कर्मचारी अभी भी कंपनी के लिए सही है। नीति और कर्मचारी के रिकॉर्ड को देखने के बाद लूना ने नौकरी खत्म करने की सिफारिश की।

आखिर एंडॉन मार्केट में एआई को कितनी जिम्मेदारी दी गई?

एंडॉन मार्केट का मकसद यह देखना है कि अगर एआई को वास्तविक कारोबार चलाने और इंसानों को संभालने की जिम्मेदारी दी जाए तो वह कितना काम कर सकता है। कंपनी ने लूना को एक लाख डॉलर, कॉरपोरेट कार्ड, इंटरनेट की सुविधा और तीन साल का लीज दिया। इसके बाद एआई को दुकान खोलकर मुनाफा कमाने का लक्ष्य दिया गया। लूना ने उत्पाद चुनने, कीमत तय करने, दुकान के खुलने का समय तय करने, ब्रांडिंग तैयार करने और कर्मचारियों की भर्ती जैसे कई काम संभाले। दुकान में किताबें, मोमबत्तियां, कलाकृतियां, खेल और दूसरे सामान बेचे जाते हैं।

इसी एआई ने कुछ दिन पहले कंपनी का कितना नुकसान कराया था?

एआई एजेंट लूना को एक रिटेल स्टोर चलाने की जिम्मेदारी जब दी गई थी, लगा था इस प्रयोग ने कंपनी नुकसान नहीं उठाएगी। लेकिन यह प्रयोग बुरी तरह फेल हो गया। एआई की गलतियों और जरूरत से ज्यादा दरियादिली के कारण स्टोर को सिर्फ चार महीने में करीब 60 लाख रुपये यानी 70 हजार डॉलर का नुकसान हुआ था।

क्या एआई से चलने वाली यह दुकान अभी मुनाफे में है?

दुकान में बिक्री तो हो रही है, लेकिन अभी तक यह मुनाफा नहीं कमा पाई है। प्रयोग शुरू होने के बाद कंपनी के बैंक खाते में मौजूद रकम भी कम हुई है। मार्च में खाते में एक लाख डॉलर थे, जो पांच महीने बाद घटकर 61,186 डॉलर रह गए। एंडॉन लैब्स के प्रमुख लुकास पीटरसन का मानना है कि यह प्रयोग बताता है कि एआई भविष्य में कारोबार और काम की दुनिया को बड़े स्तर पर बदल सकता है। हालांकि कर्मचारी को नौकरी से निकालने वाला मामला एआई की एक बड़ी सीमा भी दिखाता है। लूना नियम बना सकता था, लेकिन उसे लगातार याद रखना और लागू करना उसके लिए मुश्किल साबित हुआ।

क्या एआई आने वाले समय में इंसानों के रोजगार से जुड़े फैसले ले सकता है?

एंडॉन लैब्स का यह प्रयोग इसी सवाल को सामने लाता है। एआई को अब केवल सवालों के जवाब देने या सामग्री तैयार करने तक सीमित नहीं रखा जा रहा, बल्कि उसे कारोबार चलाने और कर्मचारियों से जुड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। इस मामले में अंतिम फैसला इंसानों ने लिया, लेकिन नौकरी खत्म करने की सिफारिश एआई ने की।

यूएस में मौसम की दोहरी मार- इंडियाना में बाढ़ से छह मौतें

वॉशिंगटन , एजेंसी। अमेरिका के इंडियाना राज्य में कई दिनों से जारी तूफान और रिकॉर्ड बारिश के बाद आई भीषण बाढ़ ने कम से कम छह लोगों की जान ले ली है। राज्य में 11 अगस्त से खराब मौसम का दौर जारी है। राजधानी इंडियानापोलिस में व्हाइट नदी का जलस्तर रविवार सुबह चरम पर पहुंच गया। सैकड़ों घरों को खाली कराया गया और तेजी से बढ़ते पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए बचाव दलों को नावों का इस्तेमाल करना पड़ा। हालांकि रविवार को बारिश कम होने और पानी उतरने के संकेत मिले।

किन लोगों की बाढ़ और तूफान में मौत हुई?- इंडियाना के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अनुसार, मृतकों में चार साल का एक बच्चा, दो पुरुष और तीन महिलाएं शामिल हैं। जेनिंग्स काउंटी में मंगलवार को तेज हवाओं के दौरान एक पेड़ बच्चे के कमरे पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। डेलावेयर काउंटी में 19 वर्षीय मैथ्यू मोरी का शव शनिवार को मिला। अधिकारियों के अनुसार, वह तीन दिन पहले दोस्तों के साथ मिसिसिनेवा नदी के तेज बहाव में पुल से कूद गया था। इसी काउंटी में 58 वर्षीय स्टेफनी सैली और उनके कुत्ते का शव भी एक खेत में मिला। माना जा रहा है कि बाढ़ वाली सड़क पर उनकी कार बह गई थी।

इंडियाना में पानी का स्तर कितना बढ़ा और कितने लोग प्रभावित हुए?- व्हाइट नदी का जलस्तर एंडरसन और नोबल्सविले इलाके में 24 फीट यानी करीब 7.32 मीटर से ज्यादा पहुंच गया। इसने 1913 में बने पुराने रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। इंडियानापोलिस के मेयर जो होगसेट ने इसे शहर में 30 साल से ज्यादा समय में आई सबसे भीषण बाढ़ बताया। राज्य में करीब 1.30 लाख बिजली उपभोक्ता रविवार दोपहर तक बिजली से वंचित थे। हालांकि यह संख्या एक समय करीब तीन लाख तक पहुंच गई थी। सड़कों और पुलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है और कई जगह तेज पानी ने रास्तों को बहा दिया।

क्या इंडियाना में अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं?

हालात में सुधार के बावजूद खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। मध्य इंडियाना के कुछ हिस्सों में रविवार को भी भारी बारिश और अचानक बाढ़ की आशंका जताई गई। लोगों से नदी और मौसम का पूर्वानुमान देखते रहने तथा तेज बहाव वाले पानी से दूर रहने को कहा गया। इंडियानापोलिस में बाढ़ के फाटकों को दोबारा खोलने की तैयारी की गई और आपातकालीन आश्रय केंद्र खुले रहे। राज्य के उत्तरी हिस्सों में पानी उतरने के बाद राहत और पुनर्वास का काम शुरू हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राज्यपाल माइक ब्रॉन के अनुरोध पर बाढ़ से राहत और बचाव के लिए संघीय आपदा सहायता को मंजूरी दे दी है।

अमेरिकी सैनिक को मारने या पकड़ने पर 30 हजार डॉलर दे रही ईरान सरकार? महिलाओं को दोगुना पैसे देने का एलान

तेहरान, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष के बीच ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने को लेकर बड़ा और विवादित एलान किया है। ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातिमी के मुताबिक, जो व्यक्ति 30 हजार डॉलर यानी करीब 28.6 लाख रुपये इनाम देने का एलान किया। ईरानी सेना प्रमुख अमीर हातिमी ने कहा है कि अगर यह काम कोई ईरानी महिला करती है तो इनाम दोगुना होकर करीब 57.2 लाख रुपये होगा। इस घोषणा ने पहले से तनावपूर्ण अमेरिका-ईरान संबंधों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस योजना को कब और कहां लागू किया जाएगा।

महिलाओं के लिए इनाम दोगुना क्यों रखा गया?- ईरानी सेना प्रमुख ने कहा कि अगर कोई ईरानी महिला ऐसी कार्रवाई करती है तो उसे दोगुना इनाम दिया जाएगा। यानी महिला के लिए घोषित इनाम 60 हजार डॉलर मतलब करीब 57.2 लाख होगा। हातिमी ने कहा कि इस योजना को बड़ी संख्या में मिले अनुरोधों और लोगों की ओर से मिल रहे समर्थन के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने इनाम की घोषणा करते हुए कार्रवाई की कोई जगह या समय नहीं बताया। इनपुट के अनुसार, ईरान के भीतर अमेरिकी जमीनी सैनिकों की कोई बड़ी तैनाती भी नहीं है।

अमेरिका और इस्त्राइल ने 28 फरवरी को तेहरान और ईरान के दूसरे हिस्सों पर हमले किए थे। इसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत का भी जिक्र किया गया है। इसके जवाब में ईरान ने इस्त्राइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। ईरानी सेना प्रमुख ने अमेरिकी सैन्य ताकत के दावों पर भी सवाल उठाया और कहा कि अमेरिका को मध्य पूर्व से हट जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका को फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में प्रवेश की अनुमति नहीं है।

युद्धविराम के बावजूद क्या तनाव कम नहीं हुआ?

अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को हुए इस्लामाबाद समझौते के तहत अस्थायी युद्धविराम और आगे स्थायी समाधान के लिए बातचीत पर सहमति बनी थी। यह समझौता 28 फरवरी से 40 दिन तक चली लड़ाई के बाद हुआ था। हालांकि, युद्धविराम नाजुक बना हुआ है और बातचीत आगे नहीं बढ़ी है।

इसके बजाय दोनों पक्षों के बीच रुक-रुककर हमले हुए हैं। दिए गए विवरण के अनुसार, संघर्ष मुख्य रूप से दक्षिणी ईरान और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास केंद्रित रहा है। अब तक 17 अमेरिकी सैन्यकर्मियों के मारे जाने की बात कही गई है और बताया गया है कि सभी की मौत ईरान के बाहर हुई।

110 वर्ष की बुजुर्ग की लंबी उम्र का राज- ताजी हवा, सेहतमंद खाना और अपना शौक जिंदा रखना

लंदन, एजेंसी। अगर आपको 110 वर्ष के किसी बुजुर्ग से रूबरू कराया जाए तो मन में सबसे पहला सवाल क्या उठेगा? जाहिर है, आखिर इनकी लंबी उम्र का राज क्या है। लोग सुपरसेंटेनेरियन यानी 110 की उम्र तक कैसे पहुंचते हैं, यह तो आज भी वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बना हुआ है। लेकिन कुछ ही समय पहले 110 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले बुजुर्गों के क्लब में शामिल हुई कैथरीन हेजेस ढेर सारी शुद्ध हवा, अच्छे खाने और अपने शौक को जिंदा बनाए रखने को अपनी लंबी उम्र का राज बताती हैं। कैथरीन का जन्म 8 जुलाई 1916 को आयरलैंड के काउंटी लिमरिक में हुआ था। 1944 में 28 वर्ष की उम्र में दुनिया घूमने निकलीं कैथरीन जब इंग्लैंड के बर्कशायर पहुंचीं तो यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहीं बसने का फैसला कर लिया। यहीं उनकी मुलाकात लेस्ली विलियम हेजेस से हुई, जो फ्रेट ट्रांसपोर्ट मैनेजर थे। फिर दोनों ने शादी कर ली। कैथरीन पेशे से एक क्वालीफाइड बुककीपर थीं और स्थानीय सरकार के कामकाज से जुड़ी रही हैं।

डेलीमेल की रिपोर्ट के मुताबिक, 16 वर्ष पहले उनके पति का निधन हो चुका है और फिलहाल वह हैम्पशायर के एक केयर होम में रहती हैं। यहीं पर पिछले महीने उनका 110वां जन्मदिन मनाया गया। कैथरीन ने अपना जन्मदिन अपने पसंदीदा गमले में लगे पेरूवियन लिली के पौधे के पास बैठकर बिताया। कैथरीन हमेशा सक्रिय रही हैं और उन्हें खुली हवा में रहना बहुत पसंद है। वह बताती हैं कि उन्हें हमेशा घर का अच्छा खाना पसंद रहा है। उन्हें घुड़दौड़ देखने का भी शौक है, जब पति जीवित थे तो दोनों साथ में टीवी पर रेस देखते थे। कैथरीन आज भी ग्रैंड नेशनल घुड़दौड़ देखती हैं और केयर होम के स्टाफ को बताती हैं कि किस घोड़े के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है।

भारतीय ने एक्स पर किया ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर झूठा दावा, अमेरिका से इजरायल तक मचा हड़कंप

यरुशलम। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष अब केवल आसमान या होर्मुज तक सीमित नहीं रह गया है। मिसाइलों और ड्रोन हमलों की सुर्खियों के बीच सोशल मीडिया पर मीम्स और फेक न्यूज के माध्यम से एक शांत लेकिन खतरनाक लड़ाई चल रही है। आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला अब वास्तविक समय में युद्ध और रुकी हुई युद्धविराम वार्ता को भी प्रभावित कर रहा है।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक सनसनीखेज और असत्यापित दावा इंटरनेट के एक अनजान कोने से शुरू हुआ। कुछ ही घंटों में यह खबर इजरायल और अमेरिका के प्रमुख समाचार माध्यमों के फ्रंट पेज तक पहुंच गई। यहां तक कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने भाषण में इसका जिक्र किया और संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप प्रशासन के राजदूत माइक वाल्ट्ज ने भी इसे साझा किया।

वायरल पोस्ट में दावा किया गया था कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कमांडर जनरल अहमद वाहिदी ने कहा है कि उनका देश तब तक परमाणु हथियार बनाने की अपनी कोशिशें नहीं छोड़ेगा, जब तक इजरायल और अमेरिका के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं।

इस पोस्ट के साथ जनरल की एक तस्वीर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई मशरूम क्लाउड यानी परमाणु विस्फोट के धुएं की तस्वीर थी।

भारतीय एक्स अकाउंट से हुई थी शुरुआत- द टाइम्स के अनुसार, जब इस पोस्ट के सफर की पड़ताल की, तो पता चला कि यह लगभग 1,75,000 फॉलोअर्स वाले एक भारतीय एक्स अकाउंट से शुरू हुआ था। दो घंटे के भीतर, 82,000 फॉलोअर्स वाले एक अन्य भारतीय अकाउंट ने इसका हिंदी अनुवाद साझा किया। मोसाद कमेंट्री नामक इजरायली अकाउंट ने इस दावे को और आगे बढ़ाया। हालांकि, इस अकाउंट का नाम इजरायल की खुफिया एजेंसी जैसा है, लेकिन इसका एजेंसी से कोई पुष्ट संबंध नहीं है। इस अकाउंट ने यह दिखाने की कोशिश की कि ईरान सद्भाव के साथ बातचीत करने के बजाय टालमटोल कर रहा है। आधे घंटे बाद इजरायल के चैनल 14 ने इस कथित बयान को अंग्रेजी में प्रसारित किया। प्रधानमंत्री के बेटे और राजनीतिक टिप्पणीकार याइर नेतन्याहू ने कुछ ही मिनटों में इस पोस्ट को और प्रचारित कर दिया।

इजरायली नेताओं के भाषणों तक पहुंचा फेक क्लेम

इस बात का कोई सबूत नहीं था कि कमांडर ने कभी ऐसा बयान दिया था, और न ही इस बात के कोई प्रमाण थे कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया है। इसके बावजूद यह दावा तेजी से फैलने लगा। इजरायली सोशल मीडिया अकाउंट्स ने इस फर्जी बयान को उठाया और जल्द ही वहां के एक टेलीविजन चैनल ने इसे प्रसारित करते हुए दावा किया कि यह ईरान का पहला खुला कबूलनामा है कि वह परमाणु बम बना रहा है। उसी शाम, यरुशलम में इजरायल के राष्ट्रीय कब्रिस्तान माउंट हर्जल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण में भी यह बात शामिल हो गई, जहां उन्होंने इसे ईरान के खतरनाक इरादों का सबूत बताया। वॉशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र में ट्रंप प्रशासन के राजदूत माइक वाल्ट्ज ने इस दावे को ऑनलाइन साझा करते हुए कहा कि ईरान आखिरकार वह मान रहा है जो सालों से साफ था। फ्लोरिडा के सीनेटर रिक स्कॉट ने भी इसे री-पोस्ट किया, और फॉक्स न्यूज ने भी इस फर्जी दावे को अपनी कवरेज में शामिल किया।

ईरान ने किया दावे को खंडन

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इस वायरल पोस्ट को इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ झूठ की बाढ़ का एक उदाहरण बताकर पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने बिना कोई सबूत दिए इस तरह के दावों के पीछे इजरायल का हाथ होने का आरोप लगाया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने के लिए दो दशकों से इसी तरह के झूठे आरोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ज्ञात हो कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर तीन दशकों से अंतरराष्ट्रीय जांच हो रही है, हालांकि तेहरान का हमेशा से यही कहना है कि यह केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है। यह परमाणु कार्यक्रम उन प्रमुख कारणों में से एक था जिसका हवाला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ अपने अभियानों को सही ठहराने के लिए देते हैं।

जैसे ही इस दावे की सच्चाई पर सवाल उठने लगे, माइक वाल्ट्ज की पोस्ट को बिना कोई स्पष्टीकरण दिए चुपचाप एक्स से हटा दिया गया। यह पूरी घटना इस बात को दर्शाती है कि कैसे एक अनजान अकाउंट द्वारा गढ़ा गया एक फर्जी बयान कुछ ही घंटों में सीमाओं और भाषाओं की बाधाओं को पार कर सकता है। इससे पहले कि कोई इसकी सत्यता को सत्यापित कर पाता, इसने सर्वोच्च स्तर पर राजनीतिक बयानबाजी की दिशा ही तय कर दी।

किम से दोस्ती, सियोल से दूरी; ट्रंप ने दक्षिण कोरिया संग युद्ध अभ्यास कम करने का दिया आदेश

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास को काफी हद तक कम करने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने इसके पीछे ईरान के खिलाफ अमेरिकी प्रयासों में दक्षिण कोरिया के सहयोग से इनकार और उत्तर कोरिया को अभ्यासों से मिलने वाले कथित दुश्मनी भरे संकेत को वजह बताया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब उत्तर कोरिया ने फिर से बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण शुरू किए हैं और अमेरिका-दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यासों को आक्रामक कार्रवाई की तैयारी करार दिया है। ट्रंप का रुख उनके उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ संबंध सुधारने और भविष्य में बातचीत फिर शुरू करने की इच्छा को भी दर्शाता है।

उत्तर कोरिया का व्यवहार बिना किसी खतरे वाला और सम्मानजनक रहा है।

दक्षिण कोरिया के इनकार से नाराज हैं ट्रंप- ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति से ईरान को परमाणु-मुक्त करने की अमेरिकी कोशिशों में शामिल होने के लिए कहा था, और उन्होंने कहा, नहीं, धन्यवाद! अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इस हफ्ते शुरू होने वाले अभ्यास न केवल महंगे हैं, बल्कि उत्तर कोरिया को पूरी तरह अनुचित और दुश्मनी भरा संकेत भी देते हैं। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में उनके कार्यकाल के दौरान उत्तर कोरिया का व्यवहार बिना किसी खतरे वाला और सम्मानजनक रहा है।

अभ्यास रद्द करने में देर, इसलिए कटौती का फैसला- ट्रंप ने लिखा, इसलिए, और इस तथ्य को देखते हुए कि इन्हें रद्द करने में अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ को संयुक्त सैन्य अभ्यास को काफी हद तक कम करने का निर्देश दिया है! यह कदम इस बात का ताजा उदाहरण है कि राष्ट्रपति अपने सहयोगी देश के बजाय उस नेता का पक्ष ले रहे हैं, जिसे पिछली सरकारों ने दुश्मन माना था। ट्रंप और उनके प्रशासन के अन्य लोगों ने ईरान के खिलाफ उनकी लड़ाई में समर्थन की कमी को लेकर नाटो सहयोगियों की भी आलोचना की है, जबकि वे बाल्टिक क्षेत्र में तेजी से आक्रामक हो रहे रूस का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिकों की भागीदारी वाले इन 11 दिवसीय अभ्यासों की योजना उत्तर कोरियाई खतरों के खिलाफ तैयारी को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। अमेरिकी सेना ने कहा है कि गर्मियों में होने वाले उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गठबंधन की मुख्य भूमिका को मजबूत करते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया गणराज्य के बीच अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। अमेरिकी सेना के अनुसार, अमेरिका और दक्षिण कोरियाई सेनाओं को जटिल परिस्थितियों में संयुक्त अभियानों का अभ्यास करना था। इनमें संयुक्त सटीक लक्ष्य-भेदन और युद्धाभ्यास की जांच के लिए लाइव-फायर अभ्यास, वेट गैप क्रॉसिंग (पानी वाली बाधा पार करना) और पहले से तैनात सैन्य उपकरणों का वितरण शामिल था। यह संयुक्त प्रशिक्षण ऐसे समय में शुरू होने वाला है, जब उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण गतिविधियां फिर से शुरू कर दी हैं, जिन पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा रखा है। इस महीने की शुरुआत में दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने उत्तर कोरिया से कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के प्रक्षेपण का पता लगाया था।

परमाणु और मिसाइल जखीरा बढ़ा रहा उत्तर कोरिया

2019 में ट्रंप के साथ किम की अहम बातचीत नाकाम होने के बाद से ही उत्तर कोरिया अपने परमाणु और मिसाइल हथियारों के जखीरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जानकारों का मानना है कि किम को लगता है कि हथियारों का बड़ा जखीरा होने से भविष्य की बातचीत में अमेरिका से ज्यादा रियायतें हासिल करने की उनकी संभावना बढ़ जाएगी।

अमेरिका-दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया की धमकी

शुक्रवार को उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने की धमकी दी। उसने उनके सैन्य अभ्यासों को आक्रामक युद्ध की रिहर्सल बताया, जिससे इलाके में अस्थिरता बढ़ रही है। यह चेतावनी उसी तरह की सख्त बयानबाजी का हिस्सा थी, जो उत्तर कोरिया अक्सर अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बड़े सैन्य अभ्यासों से पहले करता है। जानकारों का कहना है कि उत्तर कोरिया अक्सर अपने विरोधियों के सैन्य अभ्यासों का बहाना बनाकर हथियारों के जखीरे को बढ़ाने के लिए परीक्षण गतिविधियां तेज करता है और अपने अलग-थलग नेता के लिए जनता का समर्थन जुटाता है।

रूस-यूक्रेन जंग में लक्ष्मी मित्तल की फैक्ट्री बनी निशाना- प्लांट पर मिसाइलों की बौछार; दो की मौत, उत्पादन ठप

मास्को/कीव , एजेंसी। यूरोप में जारी जंग के बीच रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के गृहनगर क्रिवी रिह में भारतीय मूल के अरबपति लक्ष्मी मित्तल की आर्सेलरमित्तल माइनिंग एंड मेटलर्जिकल कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल हमला किया। यूक्रेन की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड स्टील यूनिट पर हुए इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 कर्मचारी घायल हुए हैं। मुख्य ऊर्जा और ब्लास्ट-फर्नेस ऑपरेशंस को नुकसान पहुंचने के बाद फैक्ट्री में उत्पादन आंशिक रूप से रोकना पड़ा। यह हमला यूक्रेन की ओर से रूस पर किए गए बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों के जवाब में हुआ।

यूक्रेन ने रूस पर सैकड़ों ड्रोन से किया हमला- इससे पहले यूक्रेन ने रूस पर सैकड़ों ड्रोन से हमला किया था। इसे कीव की ओर से युद्ध के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक बताया जा रहा है। इन हमलों में कम से कम छह लोगों की मौत हुई। मॉस्को क्षेत्र के गवर्नर आंद्रे वोरोब्योव ने इसे हाल के समय के सबसे बड़े ड्रोन हमलों में से एक बताया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने रातभर देश के अलग-अलग हिस्सों में 822 यूक्रेनी ड्रोन को रोका।

मॉस्को में ड्रोन हमले से 83 वर्षीय व्यक्ति की मौत

वोरोब्योव ने बताया कि मॉस्को क्षेत्र में एक निजी घर पर यूक्रेनी ड्रोन के हमले में 83 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि एक अन्य यूक्रेनी हमले के कारण पोडोल्स्क शहर में वाइल्डबेरीज के गोदाम में आग लग गई।

रोस्तोव में भी ड्रोन हमले, पांच लोगों की मौत

स्थानीय गवर्नर यूरी स्ल्यूसर ने बताया कि एक अन्य ड्रोन हमले में रूस के दक्षिण-पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र के तीन शहरों को निशाना बनाया गया। इस हमले में पांच लोगों की मौत हो गई। 150 से अधिक ड्रोन से किए गए इस हमले में कई घरों और एक रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचा, जबकि जंगल में भी आग लग गई।

युद्ध में खुल रहा नया मोर्चा

यूक्रेन ने इस साल रूस के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। लंबी दूरी की मिसाइलों और ड्रोन के झुंड के जरिए रूसी सैन्य उद्योगों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन ने लॉजिस्टिक्स कंपनी वाइल्डबेरीज के डिपो पर भी लगातार हमले किए हैं। इन हमलों में अरबों डॉलर का सामान जलकर खाक हो चुका है। ऐसे हमलों ने मॉस्को द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू किए जाने के करीब साढ़े चार साल बाद युद्ध की आंच रूसी जनता के और करीब ला दी है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

कुलगाम में ट्रक ने सीआरपीएफ के बंकर वाहन को मारी टक्कर, 5 जवान घायल

श्रीनगर (एजेंसी)। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के पांच जवान घायल हो गए। हादसा काजीगुंड के लेवडोरा इलाके में हुआ, जहां विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने सीआरपीएफ के बंकर वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बंकर वाहन पलट गया। अधिकारियों के मुताबिक, दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक संख्या जेके02डीयू-4386 ने सीआरपीएफ के बंकर वाहन जेके02सीजी-5795 को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सीआरपीएफ का बंकर वाहन सड़क पर पलट गया। इस हादसे में बंकर वाहन में सवार पांच जवान घायल हो गए। उन्हें तत्काल उपचार के लिए काजीगुंड स्थित सीआरपीएफ की 163वीं बटालियन के एमआई रूम में ले जाया गया। घायल जवानों में इंस्पेक्टर राज कुमार तिवारी, सब इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह, सहायक सब इंस्पेक्टर लोवेंडय, सहायक सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार और हेड कांस्टेबल ड्राइवर वीरेंद्र शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि सभी जवानों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों और टक्कर की परिस्थितियों की जांच शुरू कर दी है। हादसे को लेकर आगे की जानकारी का इंतजार है।

मुंबई पुलिस ने 27 वर्षीय बांग्लादेशी महिला को किया गिरफ्तार

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई पुलिस ने अवैध रूप से भारत में दुबारा प्रवेश करने और बिना वैध दस्तावेजों के शहर में रहने के आरोप में 27 वर्षीय बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। गामदेवी पुलिस थाने के अधिकारियों के अनुसार, आरोपी महिला की पहचान नादिरा सुल्ताना के रूप में हुई है, जो बिना किसी वैध यात्रा अनुमति के गैर-कानूनी तरीके से देश में रह रही थी। पुलिस को गिरगांव चौपाटी के पास एक फुटपाथ पर संदिग्ध हालत में घूमने की सूचना मिली थी। प्रारंभिक पूछताछ के दौरान जब महिला अपनी पहचान और पते से जुड़ा कोई संतोषजनक ब्यौरा नहीं दे पाई, तब बांग्लादेशी महिला को थाने लाया गया। विस्तृत जांच में उसके पास भारत में रहने का कोई भी वैध कागजात नहीं मिला। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सुल्ताना को महज एक महीने पहले ही भारत से बांग्लादेश निर्वासित किया था। हालांकि, निर्वासन के कुछ समय बाद ही वह फिर से अवैध रास्तों का इस्तेमाल कर भारत में घुसपैठ करने में कामयाब रही और मुंबई पहुंच गई। फिलहाल पुलिस इस बात की गहराई से छानबीन कर रही है कि उसने सीमा पार कर फिर भारत में कैसे प्रवेश किया और अवैध गतिविधि में उसकी मदद करने वाले अन्य लोग कौन थे। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ संबंधित कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गहन पूछताछ की जा रही है, जिसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जयराम रमेश का बड़ा आरोप : प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कहे दफनाया जाति जनगणना का विचार

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जाति जनगणना के मुद्दे पर फिर से यू-टर्न ले लिया है और बिना कुछ कहे विचार को पूरी तरह से दफन किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी को यू-टर्न का उस्ताद बताया है। कांग्रेस नेता रमेश ने आरोप लगाया कि 21 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के जरिए केंद्र सरकार ने जाति जनगणना की मांग को खारिज किया था। उस हलफनामे में कहा गया था कि यदि डिजिटल जनगणना फॉर्म में जातियों के चयन के लिए कोई ड्रॉपडाउन मेन्यू जैसी व्यवस्था होती, तब अधिक भरोसेमंद आंकड़े मिल सकते थे। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया है कि जब केंद्र सरकार ने खुद इस तरह के विकल्प की जरूरत महसूस की थी, तब आगामी जनगणना के डिजिटल प्रारूप में ऐसा ड्रॉपडाउन मेन्यू क्यों शामिल नहीं किया है। कांग्रेस नेता के मुताबिक, बिहार और तेलंगाना में हुए जाति सर्वेक्षणों से पहले इसतरह का मेन्यू पहले ही तैयार हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि पार्टी अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर ऐसी ही प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया था। कांग्रेस सांसद रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पुराने रुख से यू-टर्न लेकर जाति जनगणना कराने की बात कही थी, लेकिन अब उन्होंने विचार को ही ठंडे बस्ते में डाल दिया है।

मणिपुर में जनगणना से पहले एनआरसी लागू करने की मांग

नई दिल्ली(एजेंसी)। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में किसी भी आगामी जनगणना गतिविधि से पहले राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) लागू करने की मांग उठा दी। इंफाल लौटने के बाद उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग जनगणना के विरोध में नहीं हैं, बल्कि उनकी स्पष्ट मांग है कि पहले एनआरसी की प्रक्रिया पूरी करे और उसके बाद ही जनगणना कराए। इसके साथ ही, पूर्व सीएम बीरेन सिंह ने राज्य में जारी आर्थिक नाकेबंदी और उसके कारण जरूरी सामान की आपूर्ति में आ रही रुकावट और बढ़ती कीमतों के गंभीर मुद्दों से भी गृह मंत्री शाह को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री शाह ने इन तमाम समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान निकालने का पूरा भरोसा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि राज्य में जातीय हिंसा शुरू होने से ठीक पहले, फरवरी 2023 में उनकी सरकार ने केंद्र के समक्ष एनआरसी तैयार करने का औपचारिक प्रस्ताव रखा था। उल्लेखनीय है कि मई 2023 से राज्य में मेइती और कुकी-जो समुदायों के बीच चल रही जातीय हिंसा के कारण हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।

कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, कहा- तय हिस्से से ज्यादा पानी मिल चुका

नई दिल्ली (एजेंसी)। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की दलीलों पर सवाल उठाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी में कहा कि उपलब्ध आंकड़ों को कुल मिलाकर देखने पर ऐसा लगता है कि तमिलनाडु को उसके निर्धारित हिस्से से अधिक पानी मिल चुका है।

तमिलनाडु सरकार ने अदालत से कर्नाटक को अपने हिस्से का पानी तत्काल जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। राज्य का कहना था कि कम बारिश वाले साल में उसे कावेरी से पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है और इससे सिंचाई प्रभावित हो रही है। तमिलनाडु ने कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की अनुशंसित मात्रा और कर्नाटक से वास्तविक रूप से मिल रहे पानी को अपनी जरूरतों से कम बताया।

कर्नाटक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा कि कावेरी बेसिन में पानी की भारी कमी है। उन्होंने अदालत को बताया कि तमिलनाडु को अब तक 14.814 टीएमसी पानी मिल चुका है। उनका कहना था कि मौजूदा परिस्थितियों और अनुपात के आधार पर पानी की उपलब्धता का आकलन किया जाना चाहिए। दीवान ने यह भी बताया कि कर्नाटक ने आने वाले दिनों में कम पानी की भरपाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद पानी छोड़ने के संबंध में निर्देश दिए हैं।

दोनों पक्षों से फैक्ट शीट, एक सप्ताह बाद सुनवाई

दोनों राज्यों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पानी की उपलब्धता और आपूर्ति से संबंधित फैक्ट शीट पेश की। पीठ ने कहा कि उसने दोनों दस्तावेजों की जांच की है और मामले को एक सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। अगली सुनवाई में अदालत के सामने यह स्पष्ट किया जाएगा कि दोनों राज्यों के बीच पानी के प्रवाह और निर्धारित हिस्से की स्थिति क्या रही।

जब मैं विधायक बना तो अमित शाह बच्चे थे, वह हमें देशभक्ति सिखा रहे : खड़गे

पणजी (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जब मैं पहली बार विधायक बना था, तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। अमित शाह अक्सर सोनिया गांधी और गांधी परिवार की आलोचना करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी धर्म विरोधी हैं, क्योंकि जब मैं उत्तराखंड गया तो दो दिन बाद मंच का शुद्धिकरण कराया गया। यह शुद्धिकरण रामलीला मैदान में किया गया था, जहां खड़गे ने 8 अगस्त को भाषण दिया था। उन्होंने यह बात दक्षिण गोवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। बता दें अमित शाह ने 16 अगस्त को कहा था कि कांग्रेस पार्टी मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। बीच में ही कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने को कहा। बता दें राज्य के 12 मंत्रियों में से 10 पूर्व कांग्रेस नेता हैं, जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। गद्दारों को वोट मत दीजिए। अगर आप उन्हें वोट देंगे, तो आप भी गद्दार बन जाएंगे। बड़े शहरों के अमीर लोग गोवा में जमीन खरीद रहे हैं। क्या वे इसे आपकी भलाई के लिए खरीद रहे हैं या गोवा का मजाक बनाने के लिए। बाहर से आने वाले लोगों को जमीन खरीदकर मनमानी कीमतों पर घर बनाने और गोवा का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। गोवा में ऐसे पर्यटकों का स्वागत होना चाहिए, जो राज्य की संस्कृति का सम्मान और उसकी रक्षा करते हैं।

सीएम विजय की कर्ज माफी की घोषणा से तमिलनाडु के किसानों ने की राहत महसूस

-75 हजार रुपए तक का फसल कर्ज माफ करने का किया है ऐलान

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए फसल ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार के 100 दिन पूरे होने के मौके पर मुख्यमंत्री सी. विजय जोसेफ ने सोमवार को विधानसभा में इसकी घोषणा की है। इसके तहत सहकारी बैंकों से 75 हजार रुपए तक का फसल ऋण लेने वाले पात्र किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा।

मुख्यमंत्री विजय ने बताया कि 75 हजार रुपए तक के फसल ऋण पर किसानों को 100 प्रतिशत ऋण माफी का लाभ मिलेगा। यानी इस सीमा तक बकाया फसल कर्ज रखने वाले किसानों को पूरी राशि चुकाने से राहत दी जाएगी। सरकार ने 75 हजार रुपए से अधिक और एक लाख रुपए तक के फसल ऋण वाले किसानों के लिए भी राहत का प्रावधान किया है। ऐसे किसानों को अधिकतम 75 हजार रुपए तक की कर्ज माफी मिलेगी। इससे छोटे और सीमांत किसानों पर बकाया ऋण का बोझ कम होने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल के दौरान किसानों के हित में उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए इस योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। सरकार के इस फैसले से सहकारी बैंकों से फसल ऋण लेने वाले बड़ी संख्या में किसानों को सीधे लाभ मिलने की उम्मीद है।

अभिजीत दीपके को एनडीए में आने का मिला ऑफर

मोदी सरकार में मंत्री ने कहा- हम स्वागत करेंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के प्रमुख रामदास आठवले ने अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। हालांकि, दीपके की ओर से इस प्रस्ताव पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दीपके और सीजेपी फिलहाल सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए रखने की बात कह रहे हैं।

आठवले ने सोमवार को कहा कि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के सपने को पूरा करने तथा समाज और पार्टी को मजबूत करने के लिए दीपके को आरपीआई(ए) में शामिल होना चाहिए। दीपके ने हाल ही में राजनीति में तत्काल प्रवेश से इनकार किया था। उन्होंने हालांकि कहा था कि यदि बड़ी संख्या में लोग चाहेंगे तो वह भविष्य में इस पर विचार कर सकते हैं। जनता की मांग होने पर चुनाव लड़ने की संभावना से भी उन्होंने

इनकार नहीं किया है। सीजेपी ने जून-जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन की अगुवाई की थी। अगस्त के पहले सप्ताह में संगठन ने राष्ट्रीय कार्यसमिति का गठन किया, लेकिन स्पष्ट किया कि फिलहाल इसे राजनीतिक दल में नहीं बदला जाएगा। संगठन का कहना है कि वह चुनावी राजनीति में उतरने के बजाय जमीनी स्तर पर काम और जनजागरूकता बढ़ाने पर ध्यान देगा। दीपके ने भी कहा है कि भारत में एक और राजनीतिक पार्टी बनाना फिलहाल समाधान नहीं है। हालांकि, उन्होंने भविष्य में जनता की मांग के आधार पर अपनी भूमिका बदलने की संभावना खुली रखी है। दीपके ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले स्थित अपने पैतृक गांव से 'स्कूल ठीक करो' अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि इसका सबसे ज्यादा असर गरीब विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। उन्होंने निजी स्कूलों की फीस सीमित करने की भी मांग की। दीपके के मुताबिक, अभियान के तहत स्कूलों में पानी, खिड़कियां, बेंच और अन्य जरूरी सुविधाओं की स्थिति का आंकड़ा जुटाया जाएगा। इसके लिए एक सूची तैयार की गई है, जिसके जरिए स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभियान के अगले चरण में महाराष्ट्र के अन्य तालुकों के सरकारी स्कूलों का दौरा किया जाएगा। सीजेपी ने राजस्थान के स्कूलों में भी अभियान चलाने की योजना बताई है। संगठन सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को लेकर भी इसी तरह की मुहिम शुरू करने की तैयारी में है।

नीतीश कुमार पटना लौटते ही सक्रिय, समर्थकों ने लगाए सुपर सीएम जिंदाबाद के नारे

पटना (एजेंसी)। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य नीतीश कुमार इन दिनों सक्रिय नजर आ रहे हैं। राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेने के बाद पटना लौटे नीतीश हर दिन किसी न किसी कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। मंगलवार सुबह वे जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा के घर पहुंचे। उनके पहुंचते ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट गई। समर्थकों ने नीतीश कुमार और संजय झा के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सुपर सीएम जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए हाथ के इशारे से समर्थकों को चुप रहने के लिए कहा, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ और वे लगातार नारे लगाते रहे। संजय झा के घर पहुंचने के बाद नीतीश ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की। उन्होंने संजय झा से कहा कि अब आप आ गए हैं। सभी लोगों से मिलिए, कागज लीजिए और मेरे पास आइए। इसी दौरान संजय झा ने नीतीश कुमार को बताया कि लोगों की मांग है कि अक्टूबर से जिलों में दौरा शुरू किया जाए। इस पर नीतीश ने कहा कि पहले सब कर लीजिए। उनके इस संवाद से संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में पार्टी और संगठन से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इससे एक दिन पहले नीतीश कुमार मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। वहां मौजूद लोगों ने उनसे कहा था कि बिहार आपको बहुत मिस कर रहा है। इसके बाद से नीतीश कुमार लगातार सार्वजनिक रूप से सक्रिय नजर आ रहे हैं। राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के बाद पटना लौटे नीतीश कुमार का लगातार लोगों के बीच जाना राजनीतिक रूप से भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच उनकी सक्रियता को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है।

-किरण वेदी ने सत्ता में बैठे नेताओं को दी हिदायत

सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, सत्ता में बैठे लोगों से नागरिक सवाल पूछें

कोलकाता (एजेंसी)। रिटायर आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा है कि देश में बदलाव सिर्फ सरकार बदलने से नहीं आएगा। इसके लिए नागरिकों को सक्रिय भागीदारी निभानी होगी, सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने होंगे और मजबूत समुदाय बनाने होंगे। कोलकाता में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने नेताओं से नियमित रूप से टाउन हॉल बैठकें करने की भी अपील की। बेदी गोलपार्क स्थित रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर में आयोजित अमृता डागा मेमोरियल लेक्चर में शामिल हुईं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी केवल मतदान तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। नागरिकों को अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछने और उनकी जवाबदेही तय करने की जरूरत है।

बेदी ने कहा कि नेताओं को हर एक-दो महीने में टाउन हॉल बैठकें आयोजित करनी चाहिए, ताकि वे सीधे जनता की समस्याएं सुन सकें। उन्होंने कहा

कि ऐसी बैठकों को विरोध प्रदर्शन के तौर पर नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक, खासकर नई पीढ़ी को अपनी बात रखने और सवाल पूछने का अवसर मिलना जरूरी है। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और जनप्रतिनिधियों को समस्याओं को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने नागरिकों के लिए ईमेल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत भी बताई। बेदी ने कहा कि जब नेता वोट मांगने के दौरान जनता की सेवा का वादा करते हैं, तो नागरिकों को उनसे उनके काम और सार्वजनिक धन के इस्तेमाल पर सवाल पूछने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर लोग अपनी समस्याएं सामने नहीं रखेंगे तो समाधान की उम्मीद भी कम हो जाएगी। पूर्व पुलिस अधिकारी ने अपराध और ड्रग्स जैसी समस्याओं से निपटने में परिवारों और स्कूलों की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को समुदाय का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए स्थानीय स्तर पर लोगों की सक्रिय भागीदारी को जरूरी बताया। बेदी ने तिहाड़ जेल में अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्होंने कैदियों के पीछे अलग-अलग कहानियां देखीं और कई लोगों ने गलत फैसले लिए थे। उन्होंने कहा कि नया भारत अचानक नहीं बनेगा। यह नागरिकों और नेतृत्व की ओर से धैर्य, साहस, सतर्कता और सही फैसलों के लगातार प्रयास से तैयार होगा।

राम मंदिर दान चोरी : चंपत के साथ अनिल मिश्रा को भी क्लीन चिट

लखनऊ (एजेंसी)। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में क्लीन चिट मिल गई है। शासन को सौंपी गई रिपोर्ट में दोनों के नाम शामिल नहीं हैं। अब रिपोर्ट आगे की कार्रवाई के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेज दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, अंतिम रिपोर्ट में केवल उन आठ आरोपियों के नाम हैं, जिन्हें मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा पर सबसे ज्यादा आरोप लगे थे। दबाव बढ़ने के बाद दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित दूसरी एसआईटी मामले की जांच अभी जारी रखे हुए है।

मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर 13 जून को तीन

सदस्यीय एसआईटी गठित की गई थी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली टीम में आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव (वित्त) नील रतन कुमार शामिल थे। एसआईटी की प्रारंभिक जांच में चोरी की पुष्टि हुई थी। करीब 80 लाख रुपये की बरामदगी पुलिस को सूचना दिए बिना किए जाने की बात भी सामने आई थी। 23 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपी गई। इसके बाद 25 जून को आठ लोगों के खिलाफ श्रीराम जन्मभूमि थाने में मामला दर्ज किया गया। अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पाण्डेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अज्ञात आरोपियों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। प्रारंभिक रिपोर्ट में 27 अप्रैल से 5 जून के बीच सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 बार कर्मचारियों को नकदी छिपाकर ले जाते हुए दर्ज किए जाने की बात कही गई थी। जांच में ट्रस्ट और बैंक की संयुक्त मानक कार्यप्रणाली का पालन नहीं होने तथा प्रवेश-निकास पर तलाशी की व्यवस्था न होने का भी उल्लेख था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी एसआईटी को जांच तेजी से पूरी कर सही निष्कर्ष तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। अदालत ने जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश करने को कहा है। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद भक्तों के दान के प्रबंधन में सुधार के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर में आरक्षण विवाद गहराया, सीएम उमर ने चेताया

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल (एल-जी) द्वारा आरक्षण प्रस्ताव को मंजूरी देने में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई है और जेन-ज़ी प्रोटेस्ट जैसे विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है। उनकी कैबिनेट ने 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव पारित कर दिया है, लेकिन उपराज्यपाल की मुहर का इंतज़ार है।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति में कई बड़े बदलाव हुए हैं। 5 अगस्त 2019 को विशेष दर्जा खत्म होने से पहले, सरकारी नौकरियों में विभिन्न वर्गों के लिए 43 प्रतिशत सीटें आरक्षित थीं, जिनमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोग, पिछड़े इलाकों के निवासी, दिव्यांगजन और पूर्व सैनिक शामिल थे।

लेकिन 2024 में, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन कर सरकारी नौकरियों में आरक्षण को 43प्रतिशत से बढ़ाकर 70प्रतिशत कर दिया। यह बढ़ोतरी पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा दिए जाने के कारण हुई थी, जिसका गुर्जर और बकरवाल समुदाय ने हमेशा विरोध किया। गुर्जरों को शांत करने के लिए प्रशासन ने एसटी कोटा 10 से बढ़ाकर 20प्रतिशत करने की घोषणा की। इस फैसले से वे समूह नाराज़ हो गए जो किसी भी आरक्षण के दायरे में नहीं आते थे, क्योंकि उनके लिए केवल 30प्रतिशत नौकरियां ही बची थीं। इस पृष्ठभूमि में, उमर अब्दुल्ला की सरकार ने आरक्षण को 50प्रतिशत तक सीमित करने की सिफारिश की। एक कैबिनेट सब-कमेटी ने अक्टूबर 2025 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और अगले ही महीने उपराज्यपाल आवास (लोक भवन) भेज दिया। हालांकि, उपराज्यपाल ने इस रिपोर्ट पर कुछ सवाल उठाए थे, जिनका जवाब सरकार ने दे दिया है, लेकिन उसके बाद से इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। आरक्षण प्रस्ताव को मंजूरी न मिलने पर उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में कहा, उसके बाद क्या हुआ, कोई हमें बताए। क्या इसे मंजूरी मिल गई है? उम्मीद है कि 'जेन-ज़ी' वाला ट्रेंड यहां भी नहीं फैलेगा। इसके लिए हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। हमने अपना काम कर दिया है ज़ यह अच्छी बात नहीं है कि वे हमारी कैबिनेट के प्रस्तावों को मंजूरी देने में देरी कर रहे हैं या उन्हें दबाए हुए हैं। उन्होंने प्रशासन पर कैबिनेट के प्रस्तावों को दबाने का आरोप लगाया। इस मुद्दे ने जम्मू-कश्मीर की राजनीति में भी उबाल ला दिया है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) जैसे दलों ने आरक्षण को तर्कसंगत बनाने का वादा किया है। वहीं, बीजेपी ने अग्निवीरों और आरक्षित समूहों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का वादा किया है। उमर अब्दुल्ला को अपनी ही पार्टी के भीतर और जनता से भी

विरोध का सामना करना पड़ा है, खासकर तब जब विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों से पता चला कि कश्मीर के मुकाबले जम्मू में रिजर्वेशन कैटेगरी के ज़्यादा सर्टिफिकेट जारी किए गए थे। फिलहाल, सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर यह गतिरोध जारी है।